सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 329, नई दिल्ली । बुधवार, 05 फरवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

ज्ञान एक ऐसा दीपक है, जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है।

03 विश्व कैंसर दिवस पर सफदरजंग अस्पताल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन
06 जिन्दगी की जरूरत क्यों नहीं रहीं किताबें?
08 रेलवे के डिब्बे से 12 विस्फोटक उपकरण मिला

जब्त अनाधिकृत ई रिक्शाओं की बैटरियों को वापिस करने हेतु परिवहन विभाग को दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

संजय बाटला

डीएचसीः9725, $₹64

*नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय की तिथिः 12 दिसंबर, 2024

डब्ल्यू.पी.(सी) 12992/2024

मेसर्स अपग्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

के माध्यम सेः याचिकाकर्ता

एमआर. जयंत मेहता, एमआर. रुपेश गुप्ता, एमएस. कृतिका, एमएस. जसलीन विर्क, एडवोकेट्स विथ एमआर. विभोर निझावन, अर इन पर्सन

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य

के माध्यम सेः उत्तरदाताओं

एमएस। श्री हर्षिता नथरानी, वकील। श्री के साथ जीएनसीटीडी के लिए एएससी (सिविल) समीर वशिष्ठ। भूपिंदर सिंह, नोडल अधिकारी (स्क्रैपिंग सेल) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी

चेहराः

हों'बल एमआर. जस्टिस संजीव नरूला

संजीव नरूला, ज. (ओरल):

सीएम ए.पी.पी.एल. 73059/2024 (याचिका की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए)

1. आवेदन में बताए गए आधारों और कारणों के आधार पर, आवेदन को स्वीकार किया जाता है और वकील की सहमति से मुख्य रिट याचिका को आज ही बोर्ड में बुलाया जाता है।

2. वर्तमान आवेदन का निपटारा किया जाता है। डब्ल्यू.पी.(सी) 12992/2024

3. याचिकाकर्ता जारी करने, पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, डब्ल्यू.पी.(सी) 12992/2024, ई-वाहनों के लिए रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सिस्टम वितरित करना और बदलना, ₹बैटरी स्मार्ट₹ नाम के तहत। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित ये लिथियम-आयन बैटरियां, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए डिज़ाइन की गई तेज़ चार्जिंग, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) एकीकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) ट्रैकिंग और कंट्रोलर एरिया नेटवर्क (CAN) कार्यक्षमताओं जैसी उन्नत सुविधाओं को शामिल करती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए देश के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क का प्रबंधन करते हैं। उनके सेवा मॉडल का उद्देश्य त्वरित और सुविधाजनक बैटरी स्वैप के माध्यम से डाउनटाइम और लागत को कम करके ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

4. याचिकाकर्ताओं की शिकायत प्रतिवादियों द्वारा की गई व्यापक कार्रवाई से उत्पन्न हुई है, जिसमें कई ई-रिक्शा जब्त किए गए हैं, जो याचिकाकर्ताओं की लिथियम-आयन बैटरियों से सुसज्जित हैं। लीज-आधारित स्वैप मॉडल पर प्रदान की गई ये बैटरियां ई-रिक्शा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रतिवादियों का कहना है कि जब्त किए गए ई-रिक्शा को कानूनी मानदंडों के अनुसार उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हालाँकि, लिथियम-आयन बैटरियाँ बरामद कर ली गई हैं और अब उन्हें सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है।

5. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि लिथियम-आयन बैटरियों का स्वामित्व उनके पास है, जिन्हें कभी भी ई-रिक्शा मालिकों को नहीं बेचा गया, बल्कि उन्हें केवल पट्टे पर दिया गया था। इन आधारों पर, वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिवादियों को बैटरियों को नष्ट करने के बजाय याचिकाकर्ताओं को बरकरार वापस करना चाहिए। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने 06 सितंबर, 2024 को प्रतिवादियों को एक प्रतिनिधित्व दिया, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और विरोध किया। बाधाएँ उनकी लीज पर ली गई बैटरियों को अनुचित तरीके से नष्ट करने और उनके निपटान का प्रस्ताव दिया गया। जब प्रतिवादी इन वैध चिंताओं को दूर करने में विफल रहे, तो याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

6. प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि ई-रिक्शा को उनके एकीकृत घटकों के साथ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के गैर-अनुपालन के कारण जब्त किया गया था, विशेष रूप से वैध पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति के कारण। उन्होंने कहा कि चूंकि इन ई-रिक्शा को एक पूरी इकाई के रूप में जब्त किया गया था, इसलिए बैटरी सहित किसी भी हिस्से को स्वतंत्र रूप से छोड़ना अस्वीकार्य है। मामले की गंभीरता और नवीनता को देखते हुए, 28 अक्टूबर, 2024 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए:

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी द्वारा जब्त ई-रिक्शा की बैटरियों को छोड़ने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है। इस न्यायालय द्वारा 312/2017 में पारित 13 जनवरी, 2017 के आदेश का हवाला देते हुए, जिसके कारण ई-रिक्शा जब्त किए गए थे, प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपेक्षित पंजीकरण की कमी के कारण ई-रिक्शा जब्त किए गए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैटरियों को ई-रिक्शा के साथ एक इकाई के रूप में जब्त किया गया था, न कि अलग-अलग, उन्होंने कहा कि यदि ई-रिक्शा को अधिनियम के तहत छोड़ा जाना था, तो उन्हें बैटरियों के साथ छोड़ा जाएगा।

4. वर्तमान मामले में, ई-रिक्शा अगस्त, 2024 में जब्त किए गए थे। ई-रिक्शा के किसी भी मालिक ने वाहनों को छोड़ने के लिए आगे नहीं आया है। याचिकाकर्ताओं की आशंका है कि प्रतिवादी जब्त ई-रिक्शा की बैटरियां नष्ट करने की प्रक्रिया में हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री जयंत के. बताते हैं कि बैटरियां ई-रिक्शा मालिकों को लीज-आधारित स्वैप मॉडल पर दी जाती हैं। इस व्यवस्था के तहत, याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित स्वैपिंग स्टेशनों पर बैटरियां चार्ज की जाती हैं। ई-रिक्शा मालिक नियमित आधार पर बैटरियां बदलने के लिए उक्त स्टेशनों पर जाते हैं, जिससे याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक स्वैप के लिए एक निश्चित राशि मिलती है।

5. श्री जयंत ने आगे कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता ई-रिक्शा के संबंध में है न कि बैटरियों के संबंध में। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा जब्त की गई बैटरियां प्रतिवादियों को रिहा कर दिया जाता है, याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें केवल पंजीकृत ई-रिक्शा मालिकों को ही पट्टे पर दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता उक्त प्रभाव के लिए एक वचनबद्धता देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विचाराधीन बैटरियाँ जीपीएस से सुसज्जित अत्याधुनिक हैं, जिससे मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी ई-रिक्शा का पता लगाना आसान हो जाता है। श्री जयंत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास उनकी बैटरियों से सुसज्जित ई-रिक्शा के रिकॉर्ड हैं, और वे इसकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।

6. न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह निर्देश दिया जाता है कि श्री भूपिंदर सिंह, नोडल अधिकारी (स्क्रैपिंग सेल), परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, ताकि न्यायालय उपरोक्त मुद्दे पर संभावित समाधान पर पहुंच सके।

7. 19 नवंबर, 2024 को पुनः अधिसूचित करें।"

7. याचिकाकर्ताओं ने इन दावों का जवाब अपने अभिनव लीज़-आधारित बैटरी स्वैपिंग मॉडल की व्याख्या करके दिया। इस व्यवस्था के तहत, ई-रिक्शा मालिकों के पास कभी भी बैटरियाँ ₹स्वामित्व₹ नहीं थीं; वे केवल सदस्यता के आधार पर उनका उपयोग करते थे। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग और पंजीकरण की आवश्यकताएँ वाहनों पर लागू होती हैं, न कि बैटरियों पर। फिर भी, याचिकाकर्ताओं ने एक उपयुक्त वचन देने की पेशकश की कि अब से, केवल पंजीकृत और फिटनेस अनुपालन करने वाले ई-रिक्शा मालिकों को ही उनकी लीज़ की गई बैटरियाँ मिलेंगी। तदनुसार, 19 नवंबर, 2024 को, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के नोडल अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आगे अंतरिम निर्देश देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

1. पूर्व निर्देशों के अनुसार, श्री भूपिंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (स्क्रैपिंग सेल), परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 2000 ई-रिक्शा को स्क्रैप के रूप में बेचा गया है और ऐसे ई-रिक्शा की बैटरियों को भंडारण में रखा गया है और उनके निपटान की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उक्त बैटरियां लिथियम-आयन बैटरियां हैं, जो ई-कचरा बनाती हैं और उनके निपटान के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

2. श्री सिंह ने आगे बताया कि परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा जब्ती अभियान जारी है तथा ई-रिक्शाओं को जब्त किया जा रहा है। नियमित आधार पर जब्त किया जाता है। उन्होंने अदालत को बताया कि अगर वाहन बिना पंजीकरण या वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाता है, जिसे वाहन मालिक द्वारा परिवहन विभाग से समय-समय पर लेना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दो साल की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि, उसके बाद इसे सालाना आधार पर नवीनीकृत करना आवश्यक है।

3. ई-रिक्शा मोटर वाहन अधिनियम, 19882 के तहत निर्धारित ₹मोटर वाहन₹ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और सार्वजनिक सड़कों पर चलने की अनुमति देने से पहले उन्हें परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। विचार के लिए उठने वाला प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या लिथियम-आयन बैटरियाँ, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा ई-रिक्शा मालिकों को कथित रूप से पट्टे पर दिया जाता है, को ई-रिक्शा से अलग किया जा सकता है।

4. इस पहलू पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत के. मेहता से लागू नियमों और विनियमों के बारे में पूछताछ की थी। जवाब में श्री मेहता ने कहा कि वे अगली सुनवाई पर इस मुद्दे की जांच करें और दलीलें सुनें। 5. इस बीच, प्रतिवादी जब्त किए गए ई-रिक्शा से बरामद लिथियम-आयन बैटरियों का निपटान नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता से, न्यायालय की अनुमति के बिना।

6. 9 दिसंबर, 2024 को सूचीबद्ध करें।₹

8. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री जयंत मेहता ने तर्क दिया कि वे निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करते हैं:

8.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमवीएल अनुभाग) ने 12 अगस्त, 2020 को बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में एक संचार जारी किया है। यह संचार स्पष्ट करता है कि बिना बैटरी वाले वाहनों को परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र के आधार पर बेचा और पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, ई-रिक्शा को जब्त करने का मतलब यह नहीं है कि ई-रिक्शा में लगी बैटरियों को अलग नहीं किया जा सकता है।

8.2 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के नियम 3(के) के अनुसार,

2 ₹मोटर वाहन अधिनियम₹

₹जीवन समाप्ति बैटरी₹ को 'ऐसी बैटरी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग किया जा चुका है, जिसका इच्छित उपयोग पूरा हो चुका है और जिसे नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।' इसलिए, विचाराधीन बैटरियों को उक्त नियमों में परिभाषित 'जीवन समाप्ति बैटरियों' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, प्रतिवादियों की ज़ब्ती कार्रवाई के कारण बैटरियाँ काफ़ी हद तक खराब हो गई होंगी, फिर भी, बैटरियों में अभी भी जीवन है और याचिकाकर्ता द्वारा अन्य प्रमाणित ई-रिक्शा मालिकों को पट्टे पर देकर उनका उपयोग किया जा सकता है।

8.3 सरकार ने 'ड्राफ्ट बैटर स्वैपिंग पॉलिसी' पेश की है, जो बैटरी को सेवा के रूप में (BaaS) व्यवसाय मॉडल की व्यापक छतरी के नीचे बैटरी स्वैपिंग को मान्यता देती है, जिसके तहत ईवी को बैटरी के बिना खरीदा जा सकता है, इस प्रकार वाहन समयरेखा के दौरान बैटरी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को नियमित सदस्यता शुल्क का भुगतान करके अग्रिम लागत कम हो जाती है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का व्यवसाय मॉडल ऐसा है कि ई-रिक्शा मालिकों ने बैटरियों को पट्टे के आधार पर लिया है और याचिकाकर्ताओं और ई-रिक्शा मालिकों के बीच समझौते के अनुसार समय-समय पर उनकी अदला-बदली की जा रही है।

8.4 उपरोक्त विनियमों के प्रकाश में, स्पष्ट रूप से, बैटरी एक अलग इकाई है जिसे ई-रिक्शा से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार, बैटरियों के नष्ट होने से न केवल याचिकाकर्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि ई-कचरा पैदा करने में भी बहुत योगदान होगा।

8.5 याचिकाकर्ताओं के पास बैटरियों की पहचान करने के लिए दस्तावेज हैं, जिनकी जांच संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। ये सभी बैटरियाँ विशिष्ट अनुबंधों के तहत पट्टे पर दी गई थीं और चालान, अनुबंधों और जीपीएस ट्रैकर/स्कैनर के माध्यम से पहचानी जा सकती हैं।

9. प्रतिवादियों की वकील सुश्री हर्षिता नाथरानी ने इसका पुरजोर विरोध किया

3 ₹मोर्थ₹

तत्काल रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि:

9.1 12 अगस्त, 2020 को MoRTH द्वारा जारी संचार, जो बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है, विशेष रूप से परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए गए एक प्रकार के अनुमोदन प्रमाणपत्र का उल्लेख करता है। हालाँकि, जिन ई-रिक्शा को ज़ब्त किया गया है, उनके संबंध में ऐसा कोई प्रकार का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में दिल्ली में बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। स्क्रैपिंग के लिए ज़ब्त किए गए ई-रिक्शा अपंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जो बिना किसी वैध फिटनेस/अनुमोदन प्रमाणपत्र के सड़कों पर चल रहे थे और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे।

9.2. अपंजीकृत और अनुपयुक्त वाहनों को बैटरियाँ पट्टे पर देना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। याचिकाकर्ता द्वारा ई-रिक्शा को बैटरियाँ पट्टे पर देने की कार्रवाई, जिनके पास वैध पंजीकरण या सड़क पर चलने की योग्यता का प्रमाणन नहीं था, सार्वजनिक कल्याण के लिए हानिकारक हो सकती है और इसे ऐसे अपंजीकृत वाहनों के अवैध संचालन में सहायक के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ निजी पक्षों के बीच अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

9.3 यदि याचिकाकर्ताओं को ई-रिक्शा मालिकों को बैटरियाँ पट्टे पर देने के कारण कोई नुकसान हुआ है, तो उनके पास उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करके पट्टेदारों से हर्जाना मांगने का उपाय है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही के माध्यम से उक्त बैटरियों को मुक्त करने का उपाय उचित नहीं है।

9.4 प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई स्क्रैपिंग प्रक्रिया, याचिकाकर्ता को अपनी बैटरियों की सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने और अपनी बोलियां लगाकर उन्हें खरीदने की अनुमति देती है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

10. ई-रिक्शा जो पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, सुलभ और किफायती अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरे हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में उनकी उपयोगिता के अलावा, ई-रिक्शा आजीविका पैदा करने और ड्राइवरों के लिए आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से कई समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित हैं। हालाँकि, न्यायालय ई-रिक्शा के अनियंत्रित प्रसार के बारे में राज्य की वैध चिंताओं को स्वीकार करता है। ये वाहन, लाभकारी होते हुए भी, सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियमन की आवश्यकता रखते हैं। नतीजतन, अपंजीकृत या गैर-अनुपालन वाले ई-रिक्शा को जब्त करने का अभियान राज्य के नियामक जनादेश के अनुरूप है। जैसा कि पहले के आदेश में उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में जब्ती की कार्रवाई संबंधित वाहनों के लिए पंजीकरण या आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्रों की कमी से उपजी है।

11. तथापि, न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दा जब्ती की वैधता नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है कि क्या जब्त किए गए इन ई-रिक्शाओं में लगी बैटरियों को अलग किया जा सकता है और क्या बैटरियों पर याचिकाकर्ता के स्वामित्व अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है।

12. न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि ई-रिक्शा की बैटरियाँ रिचार्जेबल होने के कारण वाहन के संचालन के लिए अभिन्न अंग हैं, तथा इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने तथा वाहन की विद्युत प्रणालियों को सहारा देने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इसलिए, यह निर्विवाद है कि ई-रिक्शा में लिथियम-आयन बैटरियाँ वाहनों का एक आवश्यक तथा कार्यात्मक घटक हैं। हालाँकि, न्यायालय इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि बैटरियों को विनियामक तथा स्वामित्व उद्देश्यों के लिए ई-रिक्शा से अलग पहचाना जा रहा है। MoRTH द्वारा जारी 12 अगस्त, 2020 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-रिक्शा में लिथियम-आयन बैटरियाँ वाहन के लिए आवश्यक तथा कार्यात्मक घटक हैं।

इस तरह के पृथक्करण की अनुमति दी गई, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री उनकी बैटरियों से स्वतंत्र हो गई। उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:

₹नंबर आरटी 11036/72/2017-एमवीएल

भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमवीएल अनुभाग)

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, दिनांकः 12 अगस्त, 2020 को,

1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,

II. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्त।

विषयः बैटरी रहित इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री एवं पंजीकरण -रेग

सर/मैडम,

सरकार देश में विद्युतीय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है। वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल को कम करने के व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक साथ आने का समय आ गया है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा और तेल आयात बिल को कम करेगा, बल्कि उभरते उद्योग को अवसर भी प्रदान करेगा। 2. इलेक्ट्रिकल दोपहिया और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय के ध्यान में बैटरी की लागत (जो कुल लागत का 30-40% है) को वाहन की लागत से अलग करने की सिफारिशें लाई गई हैं। तब वाहन बिना बैटरी के भी बाजार में बेचे जा सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर (2W) और 3 व्हीलर (3W) की शुरुआती लागत ICE 2W और 3W से कम हो जाएगी

3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अर्थात प्रपत्र 21 (बिक्री प्रमाणपत्र), प्रपत्र 22 (निर्माता द्वारा जारी सड़क योग्यता प्रमाणपत्र) और प्रपत्र 22ए (मोटर वाहनों के लिए जारी सड़क योग्यता प्रमाणपत्र, जहां बॉडी का निर्माण अलग से किया जाता है), जो नियम 47 (मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन) के अंतर्गत मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक हैं, इनमें इंजन संख्या/मोटर संख्या (बैटरी चालित वाहनों के मामले में) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है।

4. विद्युत वाहन का प्रोटोटाइप, और बैटरी (नियमित बैटरी या स्वैपेबल बैटरी) को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों को बेचा और पंजीकृत किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण के उद्देश्य से बैटरी के मेक/प्रकार या किसी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

आपका विश्वासी डॉ. पीयूष जैन निदेशक (एमवीएल)"

13. इस विनियामक ढांचे और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन बैटरियां स्वाभाविक रूप से जब्त ई-रिक्शा से जुड़ी नहीं हैं।

14. प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि बैटरी के बिना वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है और उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है। हालाँकि, इसे सही मानते हुए भी, यह दावा याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन बैटरियों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने से नहीं रोकता है, खासकर तब जब बैटरियाँ लीज़ और स्वैपिंग मॉडल के तहत प्रदान की गई थीं जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है। याचिकाकर्ताओं के लीज़िंग समझौतों में स्वामित्व के विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। विशिष्ट लीज़िंग समझौतों के तहत याचिकाकर्ताओं ने यह स्थापित किया है कि उन्होंने बैटरियों को मालिकों को पट्टे पर दिया था। यह संविदात्मक व्यवस्था याचिकाकर्ता के बैटरियों के संबंध में विशिष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करती है। बैटरियों का विशिष्ट स्वामित्व बरकरार रहता है, भले ही वे वाहन जिनमें वे स्थापित थे, अपंजीकृत हों। इसलिए, न्यायालय को नियामक उद्देश्यों को संतुलित करते हुए इन बैटरियों के वास्तविक स्वामी के रूप में याचिकाकर्ता के विशिष्ट अधिकारों को संबोधित करना चाहिए।

15. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी अब जब्त ई-रिक्शा से बरामद बैटरियों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि जब्त वाहनों के किसी भी घटक को वापस करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। न्यायालय की राय में, ये तर्क कई कारणों से अस्थिर हैं। सबसे पहले, यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि बैटरियों को अलग करके संरक्षित किया गया है, जबकि ई-रिक्शा को नष्ट कर दिया गया है। तथ्य यह है कि प्रतिवादी इन बैटरियों को नीलाम करने की तैयारी कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत बैटरियों को 'जीवन समाप्ति बैटरी' के रूप में नहीं माना जा रहा है।

16. दूसरा, न्यायालय अनुचित बैटरी निपटान के पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। ई-रिक्शा में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों में अक्सर लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे ख़तरनाक पदार्थ होते हैं, जो अगर ठीक से न संभाले जाएँ तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बैटरियों को उनके असली मालिक या लीज़िंग कंपनी को वापस करने की अनुमति देने से न केवल ई-कचरे में कमी आएगी बल्कि उनकी उचित रीसाइकिलिंग भी आसान होगी, संसाधन संरक्षण में योगदान मिलेगा और कचरा प्रबंधन और रीसाइकिलिंग पर सरकारी नीतियों का अनुपालन होगा।

17. तीसरा, बैटरी ई-रिक्शा का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान घटक है, और लीज़िंग कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय निवेश को संरक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत लीज़िंग मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि समझौते की शर्तों के तहत बैटरियां लीज़िंग कंपनी की संपत्ति बनी रहेंगी। बैटरियां वापस करने से याचिकाकर्ता उन्हें अन्य वाहनों में पुनः उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिससे उनके निवेश का एक हिस्सा वापस मिल जाएगा।

18. प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि अगस्त 2020 MORTH संचार, जो बैटरी के बिना ईवी पर विचार करता है, एक प्रकार की स्वीकृति प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। वे बताते हैं कि प्रकार की स्वीकृति प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, अपंजीकृत और अनुपयुक्त वाहनों को बैटरी पट्टे पर देना जन कल्याण से समझौता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि जबकि राज्य की चिंताएँ वैध नियामक और प्रवर्तन विचारों को उजागर करती हैं, उन्हें याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व अधिकारों और ईवी बैटरी पट्टे के मॉडल के उभरते परिदृश्य के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रासंगिक होते हुए भी प्रकार की स्वीकृति प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति, बैटरी में याचिकाकर्ताओं की मालिकाना हिस्सेदारी को समाप्त नहीं करती है। इसके अलावा, उपयुक्त निर्देशों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य के पट्टे सभी फिटनेस और अनुमोदन मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हैं जो प्रतिवादियों द्वारा बताई गई सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करेंगे। नीलामी के माध्यम से बैटरी वापस खरीदने का उपाय, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा सुझाया गया है, स्पष्ट रूप से अनुचित और आर्थिक रूप से तर्कहीन होगा।

19. इसके अलावा, ई-रिक्शा मालिकों को बैटरी पट्टे पर देने का याचिकाकर्ता का व्यवसाय मॉडल न तो निषिद्ध है और न ही मौजूदा नियमों के विपरीत है; बल्कि, यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बैटरी स्वैपिंग नीति, हालांकि वर्तमान में मसौदा चरण में है, ईवी अपनाने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। आम तौर पर, ईवी को स्थिर बैटरी के साथ बेचा जाता है, जिसे वाहन के भीतर रखे जाने के दौरान बिजली की आपूर्ति के माध्यम से सीधे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इस सेटअप को बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अड़चन के रूप में पहचाना गया है, मुख्य रूप से विश्वसनीय और व्यापक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी के कारण। मसौदा नीति बैटरी स्वैपिंग को स्थिर बैटरी प्रणालियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पहचानती है। बैटरी स्वैपिंग डिस्चार्ज की गई बैटरियों को पहले से चार्ज की गई बैटरियों से बदलने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता बैटरियों को अलग से चार्ज कर सकते हैं और ईवी के लिए न्यूनतम डाउनटाइम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण पर आधारित याचिकाकर्ता का व्यवसाय मॉडल परिचालन लचीलेपन और दक्षता को बढ़ावा देता है।

20. संक्षेप में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ई-रिक्शा मालिकों को उनके द्वारा पट्टे पर दी गई लिथियम-आयन बैटरियों को पुनः प्राप्त करने का हकदार है। ये बैटरियाँ, जिन्हें विशिष्ट समझौतों के तहत पट्टे पर दी गई संपत्ति के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है, कभी भी ई-रिक्शा संचालकों के स्वामित्व में नहीं थीं, जिनके अपंजीकृत वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए वाहनों से इन बैटरियों को अलग करने का प्रतिवादियों का निर्णय इस अलग स्वामित्व की मान्यता को दर्शाता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, बैटरियाँ उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए।

21. पूर्वोक्त के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:

21.1 याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एक वचनबद्धता दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि अब से वे अपनी लिथियम-आयन बैटरियां केवल उन ई-रिक्शा मालिकों को पट्टे पर देंगे या आपूर्ति करेंगे जो वैध पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणीकरण का सबूत प्रस्तुत कर सकेंगे।

21.2 याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि बैटरियों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा बरामद बैटरियों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि उन बैटरियों की पहचान की जा सके जिन्हें उन्होंने विशिष्ट लीजिंग समझौतों/अनुबंधों के तहत पट्टे पर दिया था। इस उद्देश्य के लिए, प्रतिवादी के वकील प्रतिवादी के वकील के साथ समन्वय करेंगे। याचिकाकर्ताओं को ऐसे निरीक्षण के लिए तारीख और समय की सूचना देनी होगी।

21.3 बरामद बैटरियों की पहचान याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवादियों की उपस्थिति में की जाएगी। निरीक्षण के बाद पहचान की गई बैटरियाँ आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सौंप दी जाएँगी।

22. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, लंबित आवेदनों सहित वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

23. सुनवाई की अगली तारीख, यानी 20 फरवरी, 2025, रद्द की जाती है।

संजीव नरूला, ज 12 दिसंबर, 2024/ab

डब्ल्यू.पी.(सी) 12992/2024

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव, कैरियर, रोग और उपाय

ज्योतिषाचार्य पं योगेश पौराणिक

नक्षत्र मंडल में उपस्थित मुख्य रूप से दो चमकीले तारे जो कि पुरुष और प्रकृति के रूप में पुनर्वसु नक्षत्र को दर्शाते है। पुनर्वसु शब्द पुनः+वसु से बना है। जिसका अर्थ है ऊर्जा व शक्ति की पुनः प्राप्ति या पुनः यश, धन प्राप्त होना। ज्योतिषियों ने इस नक्षत्र को शुभत्व की ओर ले जाने वाला तथा प्रगतिशील बताया है। इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है तथा अधिष्ठात्री देवताओं की माता अदिति हैं। इसी कारण पुनर्वसु को देवगणों का नक्षत्र माना जाता है। वाणों से भरा हुआ तरकस ही इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है।

स्वभाव : पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक के स्वभाव में देव गुरु बृहस्पति तथा भगवान राम के गुण तथा स्वभाव की झलक देखने को मिलती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक व्यवहार कुशल, शांतचित्त, सत्यवादी व दृढ़ निश्चयी होता है। ये दिखने में मध्यम कद काठी के अनुशासित, धार्मिक व न्याय प्रिय होते हैं। आचार्य वराहमिहिर के मताअनुसार पुनर्वसु नक्षत्र के जातक भाग्यशाली, धीर, गंभीर, ज्ञानी, बुद्धिमान तथा सदाचारी होता है।

कैरियरः इस नक्षत्र में जन्मे जातक मठाधीश, ज्योतिषी, धर्मगुरु, विदेश व्यापारी, रेडियो,

टेलीविजन व दूरदर्शन कलाकार, जमीदारी, गूढ़ विधा ज्ञान, अध्यापक, एस्ट्रोनॉमी, खेल कोच, लेखक, शिल्पकर्म, न्यूजपेपर संपादक, सन्यासी आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं।

रोगः इस नक्षत्र में जन्मे जातक प्रायः वात से संबंधित दोष, छाती, फेफड़े तथा पेट से संबंधित रोग से ग्रसित देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हे कभी कभी कान तथा गले से संबंधित समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।

उपायः पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगो को देव गुरु बृहस्पति, देव माता अदिति तथा मां सरस्वती की पूजा अर्चना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। जीवन के कष्टों से मुक्ति हेतु प्रणव मंत्र ॐ का जाप करना चाहिए। जब भी गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र पड़े तब उस दिन बांस का वृक्षारोपण करें। हरा, पीला तथा सफेद रंग का प्रयोग इन्हे शुभ परिणाम देता है।

हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पेड़ है अक्षयवट, जानिए इसके धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अक्षयवट संगम के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म में यह सबसे पवित्र पेड़ों में से एक है। इस वृक्ष को अक्षय इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अमर है। अक्षयवट का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से रहा है।

इस धरती पर वैसे तो करोड़ों पेड़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं। इन पेड़ों के बारे में अद्भुत कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में पांच वटवृक्षों को विशेष महत्व दिया जाता है। इनमें पंचवट, अक्षयवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट हैं। हालांकि इनकी उम्र के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन माना जाता है कि यह बहुत प्राचीन हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अक्षयवट संगम के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म में यह सबसे पवित्र पेड़ों में से एक है। इस वृक्ष को अक्षय इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अमर है। अक्षयवट का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से रहा है। धार्मिक मान्यता है कि यह वृक्ष कभी नष्ट नहीं होगा और यह मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको अक्षय वट के धार्मिक महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं।

जानिए धार्मिक महत्व

अक्षय वट को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित होने की वजह से तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यह विशेष महत्व रखता है। माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान लाखों-करोड़ों की संख्या में भक्त इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करने और परिक्रमा करने आते हैं।

हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस वट की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य

फल की प्राप्ति होती है। महाभारत और पुराणों में अक्षयवट को ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश द्वारा संरक्षित बताया गया है। इसलिए इस वृक्ष को त्रिदेवों की कृपा का स्थान माना गया है।

पौराणिक कथा

सृष्टि की शुरूआत में महाप्रलय के दौरान जब पूरी दुनिया पानी में डूबी थी। तब अक्षय वट नामक एक वृक्ष अडिग रहा। यह अक्षयवट न सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अक्षय वट के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बालक के रूप में विराजमान थे। वह इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे थे। इस अद्भुत घटना की वजह से अक्षय वट को भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह वृक्ष न सिर्फ अपनी अमरता के लिए बल्कि भगवान के साथ इसके जुड़ाव के कारण भी पूजनीय है।

अक्षय वट को उन संतों और ऋषियों का तप करने का स्थान माना जाता है। जो मोक्ष पाना चाहते थे। माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने भी इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि इस धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी अक्षयवट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। इस वजह को ऋषभदेव तपस्थली या तपोवन के नाम से भी जाना जाता है।

वहीं जब प्रभु श्रीराम अपने वनवास के दौरान प्रयागराज पहुंचे, तो उन्होंने भी इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अनेक तपस्याएं की थी। यही वजह है कि यह स्थान रामभक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसे में वर्तमान समय में श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के चरणों में शीश झुकाने का अद्भुत अवसर मिलता है।

राजस्थान के राजपूताना वास्तुकला का शानदार उदाहरण है नीमराना किला

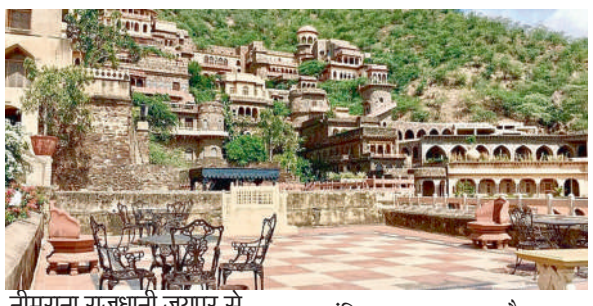

नीमराना राजधानी जयपुर से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आसानी से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली से भी यह 130 किलोमीटर दूर है, और यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक ट्रेन, बस या कार का उपयोग कर सकते हैं।

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीमराना एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन किलों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह भारतीय इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। नीमराना का किला यहां का प्रमुख आकर्षण है, जो इस स्थान को दुनियाभर में प्रसिद्ध बनाता है। आइए, जानते हैं नीमराना के बारे में कुछ रोचक जानकारी।

1. नीमराना किला

नीमराना किला, जो कि 15वीं शताब्दी का ऐतिहासिक किला है, इस स्थान का मुख्य आकर्षण है। किला राजस्थान के राजपूताना वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यह किला लगभग 12 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यहां से पूरे नीमराना शहर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। किला अब एक प्रसिद्ध होटल के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जहां पर्यटक रुक सकते हैं और इस ऐतिहासिक किले का अनुभव कर सकते हैं। किले में एक शानदार स्विमिंग पूल, स्पा, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

2. नीमराना की ऐतिहासिकता

नीमराना का इतिहास काफी रोचक और पुराना है। यह किला नीमराना परिवार द्वारा 1464 में बनवाया गया था। किले का निर्माण उस समय के राजपूत साम्राज्य के महलों और किलों के अनुकूल किया गया था। नीमराना का नाम 'नीम' (नीम के पेड़) और 'राणा' (शासक) शब्दों से मिलकर पड़ा है, और इसका एक रोमांटिक इतिहास भी है। किले का डिज़ाइन और संरचना आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

3. पर्यटन के अन्य आकर्षण

नीमराना के किले के अलावा, यहाँ कुछ अन्य आकर्षक स्थल भी हैं:

वामदेव मंदिरः यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में शांति का वातावरण और अद्भुत स्थापत्य कला देखने को मिलती है।

बीलू और सुरजकुंडः यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करने के लिए आदर्श है। यहां पर पर्यटक प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं।

नीमराना झीलः यह झील किले के पास स्थित है और पर्यटकों को यहां पिकनिक मनाने और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने का अवसर मिलता है।

4. कैसे पहुंचे नीमराना?

नीमराना राजधानी जयपुर से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आसानी से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली से भी यह 130 किलोमीटर दूर है, और यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक ट्रेन, बस या कार का उपयोग कर सकते हैं। नीमराना के पास का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन अलवर है, जो इस स्थान से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है।

5. आवास और खाने की व्यवस्था

नीमराना में विभिन्न प्रकार के होटलों और रिसॉर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें से नीमराना किला एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर्यटक ऐतिहासिक माहौल में आराम करने का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा, यहां के रेस्टोरेंट्स में राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी का आनंद भी लिया जा सकता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और राजस्थान की स्वादिष्ट मिठाइयां प्रमुख हैं।

6. सर्वश्रेष्ठ समय

नीमराना घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है। गर्मियों में यहां का तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए इस मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

नीमराना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर स्थल है, जो पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहां का किला, मंदिर, और प्राकृतिक दृश्य न केवल रोमांचक हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने का भी एक बेहतरीन अवसर देते हैं। अगर आप भी राजस्थान की खूबसूरत और ऐतिहासिक यात्रा करना चाहते हैं, तो नीमराना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

रामबाण है शहद में भिगोकर आंवला का सेवन करना, मिलते हैं कई फायदे

अच्छी सेहत होने से किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। शहद में आंवला भिगोकर खाने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं में आराम मिलता है। आइए आपको इसके फायदे बताते हैं।

आंवला सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते है। शहद और आंवला दोनों ही सेहत के लिए सुपरफूड है। आयुर्वेद में इन दोनों कॉम्बिनेशन फायदे बताएं है। इन दोनों को अपनी डाइट में जरुर शामिल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। शहद को खांसी-जुकाम के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इसके सेवन से इंफेक्शन का खतरा कम होता है। जब यह दोनो साथ खाएं जाते हैं, तो कई फायदे मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं शहद में आंवला भिगोकर खाने के फायदे।

इम्यूनिटी बूस्ट होती

अगर आप शहद में आंवला भिगोकर खाएंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आंवला में विटामिन सी मौजूद होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। वहीं, शहद में एक्टी-बैक्टीरियल गुण इंफेक्शन का खतरा कम करता है। शहद में भीगे हुए आंवले खाने के वायरल-इंफेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है।

पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है

यदि आपको भी पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके सेवन से अपच, एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके सेवन से भी गट हेल्थ भी अच्छा होता है, जिससे पाचन स्वस्थ रहता है।

गुड फॉर स्किन

आंवला और शहद का कॉम्बिनेशन स्किन हेल्थ को इंप्रूव करती है। वहीं, शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन इंफेक्शन का खतरा भी कम करता है। आंवला में विटामिन सी होता, जो कि स्किन में कोलेजन बूस्ट करने में मदद करता है।

खांसी-जुकाम में आराम मिले

सर्दियों में खांसी-जुकाम में ज्यादातर होते रहते हैं। शहद में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इसके सेवन से गले का इंफेक्शन कम होता है और कफ से भी राहत मिलती है। शहद और आंवला खांसी और जुकाम में भी राहत देता है।

बॉडी को एनर्जी मिलती है

सोकर जब आप उठते हैं तो आपको भी थकावट और कमजोरी महसूस होती है, तो आंवला और शहद जरुर खाएं। इसके सेवन से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही कमजोरी और थकावट भी नहीं होते हैं।

इसका सेवन कैसे करें

इसके लिए आपको कच्चे आंवला को शहद में भिगोकर खाना है। आंवला को टुकड़ों में काट लें। अब इसे शहद में डालकर कच्चा ही खाएं। आप चाहे तो आंवले को धूप में सूखाकर शहद में डालकर रख दें। इसमें आप काला नमक और काली मिर्च डालकर भी रख सकते हैं। रोजाना आप 2-3 टुकडें का सेवन करें। जब आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहते हैं और जो कि काफी फायदेमंद होता है।

अंडमान जाने की ट्रिप का कर रहे हैं प्लान, तो इन फेमस मंदिरों का जरुर करें दर्शन

अंडमान एक द्वीप समूह है और यह कई भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपने वास्तुकला, समुद्र तटों के पास स्थित विशेष मंदिर है, जहां आपको जरुर जाना चाहिए।

समुद्र किनारे सुकून के पल बिताने के लिए कपल्स बीचेज पर जरुर जाते हैं। अगर आप भी अंडमान जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप समुंद्र तटों के अलावा वहां के खूबसूरत और धार्मिक मंदिरों का जरुर दर्शन करें। अंडमान में नीले पानी से लेकर सफेद रेत तक समुद्र तटों तक फैली शांति कपल्स को सुकून देती है। बीचेज के साथ ही यहां पर कुछ ऐसे मंदिर भी है, जो आपको सुकून का एहसास कराते हैं। आइए आपको अंडमान में मौजूद फेमस मंदिरों के बारे बताते हैं।

मुरुगन मंदिर

पोर्ट ब्लेयर के केंद्र में स्थित यह मंदिर

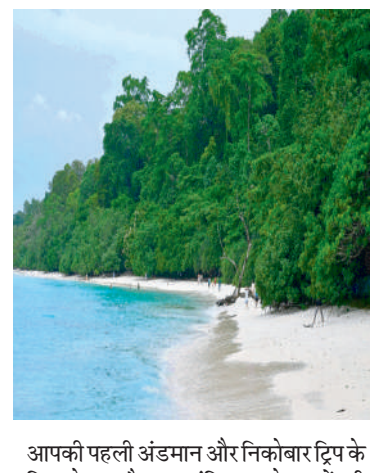

आपकी पहली अंडमान और निकोबार ट्रिप के लिए बेहतर है। यह मंदिर अपने भक्तों की आध्यात्मिक आस्था के लिए आकर्षित करते हैं, बल्कि सुंदर वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। वीकेंड पर भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं। जब जाएं तो मंदिर के समय का ध्यान रखें।

शंकराचार्य मंदिर

अगर आप अंडमान की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप इस मंदिर में जरुर जाएं। यह मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित होने की वजह से यहां का नजारा शानदार है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर जा रही हैं, तो आप यहां जरुर जाएं।

श्री गणेश मंदिर

यह मंदिर पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। श्री गणेश मंदिर सुबह 8 बजे से 10.30 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक हर दिन खुला रहता है। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यह भक्तों के लिए विश्वास का सबसे खास प्रतीक माना जाता है। यहां पर जाने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन बाजार के पास स्थित है। सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

यहां देखिए कैंसर के 10 जानलेवा रूप, जानिए कारण और बचाव के तरीके

वर्ल्ड कैंसर डे हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और इनसे कैसे अपना बचाव किया जा सकता है।

हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक अभियान है, जो हमें इस गंभीर बीमारी के प्रति सचेत रहने और समाज को जागरुक करने के लिए मनाया जाता है। वहीं सही जानकारी, हेल्दी लाइफस्टाइल और शुरूआती जांच से कैंसर को हराया जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरुक करना है। वर्ल्ड कैंसर डे हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और इनसे कैसे अपना बचाव किया जा सकता है।

कैंसर के प्रकार

बता दें कि डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने करीब 200 से ज्यादा तरह के कैंसर का पता लगाया है। इसके लक्षण अलग-अलग होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर लोगों में जल्दी फैलते हैं।

ब्लड कैंसर

आमतौर पर जिस कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है, वह ब्लड कैंसर है। इस टाइप के कैंसर में शरीर की रक्त कोशिकाओं में कैंसर जन्म लेते हैं। जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। वहीं ब्लड कैंसर बहुत तेजी के साथ पूरे शरीर में फैल जाता है।

फेफड़ों का कैंसर

फेफड़ों का कैंसर होने पर व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। इस कैंसर के होने पर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें हड्डियों-जोड़ों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बलगम जमना और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

स्किन कैंसर

पिछले कुछ समय में स्किन कैंसर के मामले सबसे ज्यादा सुने गए हैं। सबसे अधिक गर्मी में रहने की वजह से स्किन कैंसर होता है। वहीं अच्छा भोजन न करने पर भी यह कैंसर हो सकता है। हर टाइप के व्यक्ति में यह कैंसर देखा गया है।

ब्रेनकैंसर

ब्रेन कैंसर व्यक्ति के सिर में होता है। इसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। इस कैंसर में पीड़ित व्यक्ति के दिमाग वाले हिस्से में एक गांठ बन जाती है। यह गांठ समय के साथ बढ़ती है और फिर पूरे दिमाग में अपनी जगह बना लेती है।

स्तन कैंसर

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक होता है। वहीं पुरुषों में इस कैंसर का खतरा कम होता है। ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं के स्तन में गांठ बन जाती है। जो समय के साथ-साथ बढ़ती है और इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है।

मुंह का कैंसर

मुंह का कैंसर पान-मसाला और गुटका खाने वालों में ज्यादा होता है। पान-मसाला और गुटका खाने से मुंह में घाव पैदा हो जाता है। जोकि बाद में कैंसर का रूप ले लेता है।

लिवर कैंसर

खानपान में गड़बड़ी होने या फिर लिवर में बीमारी होने की वजह से लिवर कैंसर हो जाता है। इसमें लिवर में कैंसर की कोशिकाएं पैदा होती हैं, जो धीरे-धीरे लिवर को डैमेज कर देती हैं।

बोन कैंसर

बोन कैंसर हड्डियों में पैदा होता है। हड्डियों में चोट लगने की वजह से या फिर पुरानी चोट की वजह से बोन कैंसर होता है।

पेट का कैंसर

अनहेल्दी खानपान की वजह से पेट के किसी हिस्से में कैंसर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। जिसकी वजह से शरीर का कोई भाग अपना कंट्रोल खो देता है। पेट का कैंसर काफी खतरनाक होता है।

लंग कैंसर

यह कैंसर भी सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में से एक है। शराब पीने, गुटका खाने और नशीले पदार्थ लेने से लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है।

कैंसर से बचाव के तरीके

कैंसर से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बैलेंस डाइट लें और डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें।

इसके साथ ही तंबाकू और शराब का सेवन न करें।

सूरज की हानिकारक किरणों से खुद का बचाव करें।

समय-समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहें।

तनाव से बचें और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें।

"काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है"

काशी को स्वयं भगवान शिव ने 'अविनाशी' और 'अविमुक्त क्षेत्र' कहा है। ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्वरूप होने के कारण प्रलयकाल में भी काशी नष्ट नहीं होती है; क्योंकि प्रलय के समय जैसे-जैसे एकार्णव का जल बढ़ता है, वैसे-वैसे इस क्षेत्र को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर उठाते जाते हैं।

स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल के आकार का, त्रेता में चक्र के आकार का, द्वापर में रथ के आकार का तथा कलियुग में शंख के आकार का होता है।

संसार की सबसे प्राचीन नगरी है काशी

काशी को संसार की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है; क्योंकि वेदों में भी इसका कई जगह उल्लेख है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहले यह भगवान माधव की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरने से वह स्थान 'बिंदु सरोवर' बन गया और भगवान यहा 'बिंदुमाधव' के नाम से प्रतिष्ठित हुए।

एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्माजी का पांचवा सिर अपने नाखूनों से काट दिया। तब वह कटा सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। वे १२ वर्षों तक बदरिकाश्रम, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमते रहे, परंतु वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। ब्रह्मदेव का सिर काटने से ब्रह्महत्या स्त्री रूप धारण करके उनका पीछा करने लगी।

अंत में जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और स्नान करते ही उनके हाथ से चिपका हुआ कपाल भी अलग हो गया। जिस स्थान पर वह कपाल छूटा, वह 'कपालमोचन तीर्थ' कहलाया। तब शंकर जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया"

जय भोले बाबा की

सुशासन, शिक्षा और नवाचार मिलकर एक बेहतर दिल्ली बना सकते हैं: उपराज्यपाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली, स्मार्ट गवर्नेंस केवल नीतियों और प्रशासन तक सीमित नहीं है; यह उन विचारों के बारे में है जो धरातल पर वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यह बात दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईपी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025' के भव्य समापन समारोह में कही। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में यातायात जाम, कचरा प्रबंधन की समस्या, वायु प्रदूषण, जल संकट और महिलाओं की सुरक्षा जैसी शहरी चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए किया गया था।

प्रतियोगिता में जीत हासिल करना सराहनीय है, लेकिन दिल्ली की प्रगति में योगदान देना ही वास्तविक उपलब्धि है। यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है—जहां शासन, शिक्षा और नवाचार एक साथ मिलकर एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए कार्य करेंगे। हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा, नवाचार को अपनाना होगा और विचारों को कार्यान्वित करने के संकल्प के साथ काम करना होगा। उपराज्यपाल ने विज्ञान भवन में मौजूद 1300 से अधिक छात्रों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।

आइडियाथॉन के विजेताः

आइडिएटर्स, अस्तित्व और MBCL (महिला बचाओ चश्मा लगाओ) को 'स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025' के विजेता घोषित किया गया। प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को उपराज्यपाल ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ क्रमशः 3 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त, सात सांत्वना पुरस्कार के रूप में 20,000/- रुपये प्रत्येक दिए गए। प्रत्येक थीम में तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली टीमों को क्रमशः 10,000/- रुपये और 7,000/- रुपये का पुरस्कार दिया गया।

'स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025' का उद्देश्य कुछ सबसे प्रतिभाशाली युवा दिमागों को एक मंच प्रदान करना था, ताकि वे नवाचार, प्रौद्योगिकी और नए दृष्टिकोणों के साथ शहरी समस्याओं का समाधान खोज सकें।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा ने दिल्ली के छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को केवल एक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 1008 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 148 दूसरे दौर में पहुंच सकीं और अंत में 10 टीमें फाइनल राउंड में अपने विचार प्रस्तुत करने में सफल रहीं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सतत और प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्यता है।

यातायात जाम और पार्किंग की समस्या लंबे समय से शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जिससे देरी, तनाव और प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रतियोगिता में ट्रैफिक हाइव नामक समाधान प्रस्तुत किया गया, जो यातायात सिग्नलों को सिंक्रोनाइज़ करके और वास्तविक समय में पार्किंग की जानकारी देकर शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा।

कचरा प्रबंधन भी एक गंभीर समस्या है, जहां प्रतिदिन हजारों टन कचरा जमा होता है। युवा नवाचारियों ने एआई-आधारित मॉडल प्रस्तुत किए, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने को बढ़ावा देते हैं। इसमें स्मार्ट बिन, गेमिफिकेशन और डिजिटल प्रोत्साहन का उपयोग किया गया, जिससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जेनेटिकली एडवांस्ड शैवाल पैनल आधारित बायोलॉजिकल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का सुझाव दिया गया, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना अधिक प्रदूषकों को अवशोषित कर सकता है।

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआई-सक्षम स्मार्ट ग्लास पेश किए गए, जो वास्तविक समय में संकट संकेत भेज सकते हैं। इसके अलावा, सीसीटीवी सर्विलांस और आईओटी सेंसर के माध्यम से भविष्यवाणी-आधारित अपराध विश्लेषण तकनीकें प्रस्तावित की गईं, जो सुरक्षा और कानून प्रवर्तन की दक्षता को बढ़ाने में मदद करेंगी।

प्रतियोगिता का आयोजन एवं सहयोगः

इस पहल को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा समर्थन दिया गया और इसे विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन और इनोवेशन फंड तथा AICTE आइडिया लैब के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय प्रो. अमित प्रकाश सिंह और प्रो. अजय सिंघोली ने किया।

इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा, उच्च शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव नंदिनी पालीवाल, और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

सऊदी फिल्म आयोग ने भारत में सऊदी फिल्म नाइट्स की शुरुआत की

सुषमा रानी

सऊदी फिल्म आयोग, डोम एंटरटेनमेंट, एक प्रमुख भारतीय प्रोडक्शन और इवेंट कंपनी के सहयोग से, सऊदी फिल्म नाइट्स को भारत में लेकर आया है। यह पहल मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के जीवंत शहरों में सऊदी अरब के सिनेमाई डेब्यू को चिह्नित करती है। भारत में सऊदी फिल्म नाइट्स मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया और चीन में पहले आयोजित सफल स्क्रीनिंग के बाद हो रही है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब के उभरते फिल्म उद्योग को दिखाया जाएगा।

भारत में सऊदी फिल्म नाइट्स में सऊदी फिल्मों का एक चुनिंदा चयन दिखाया जाएगा, जिसमें साद ताहैता की "मशनिया लाइफ" और अहमद अलकितमी की "द एज" जैसी लघु फिल्में और मंसूर असद की "स्लेव" जैसी फीचर फिल्में और साथ ही फारिस गोडस की "फीवर ड्रीम" शामिल हैं।

भारतीय दर्शक सऊदी फिल्म निर्माताओं के साथ स्क्रीनिंग के बाद विशेष चर्चा का आनंद लेंगे, जो सऊदी सिनेमा को आकार देने वाली रचनात्मक यात्राओं और सांस्कृतिक कथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य भारतीय और सऊदी फिल्म उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी विकास को बढ़ावा देना है। डोम एंटरटेनमेंट के संस्थापक मोहम्मद मोरानी और मजहर नाडियाडवाला ने कहा, ₹हम इन असाधारण फिल्मों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सऊदी फिल्म आयोग के साथ सहयोग करने को लेकर उत्साहित हैं। यह साझेदारी न केवल सऊदी अरब की कलात्मक प्रतिभाओं को उजागर करती है, बल्कि भविष्य के सहयोग के लिए भी द्वार खोलती है, जो हमारे दोनों सिनेमाई परिदृश्यों को समृद्ध करेगी।₹ यह भारत में सऊदी फिल्म आयोग की पहली उपस्थिति नहीं है, क्योंकि इसने पिछले नवंबर में गोवा में फिल्म बाजार के 18वें संस्करण में भाग लिया था। भागीदारी में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल थीं, जिसमें सऊदी सिनेमा में विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक मंडप, साथ ही ₹सऊदी फ़िल्में निर्माण में₹ शीर्षक से एक सत्र की मेजबानी भी शामिल थी।

सऊदी फ़िल्म आयोग सऊदी संस्कृति मंत्रालय के तहत 11 विशेष आयोगों में से एक है, जिसका उद्देश्य फ़िल्म निर्माताओं का समर्थन करके, सऊदी फ़िल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देकर और राज्य के भीतर एक संपन्न सिनेमाई संस्कृति का पोषण करके सऊदी सिनेमा के विकास को बढ़ावा देना है। सऊदी फ़िल्म नाइट्स जैसी पहल फ़िल्म निर्माताओं के बीच पुल बनाने, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लक्ष्मी नगर विधानसभा में वकार चौधरी की मजबूत दावेदारी, जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर इस बार बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी मो. वकार चौधरी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वकार चौधरी न केवल समाज में मजबूत मुस्लिम नेतृत्व को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे एक ऐसे जननेता हैं, जो हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं।

वकार चौधरी सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच नहीं आते, बल्कि उन्होंने हमेशा समाज सेवा को अपना धर्म समझा है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों की भोजन, दवाई और आर्थिक सहायता करके उनकी मदद की। साथ ही, वे लगातार गरीबों और वंचितों की सहायता में जुटे रहते हैं।

वकार चौधरी ने हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। चाहे क्षेत्र में जर्जर सड़कों की मरम्मत का मामला हो, जल निकासी की समस्या हो, या बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई, उन्होंने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। वे केवल आश्वासन नहीं देते, बल्कि उनके द्वारा कई आंदोलनों के माध्यम से प्रशासन को मजबूर किया गया कि जनता की मांगें पूरी की जाएँ। एक सफल व्यापारी और लक्ष्मी नगर के प्रमुख बाजार संघों के प्रधान के रूप में, वकार चौधरी ने हमेशा छोटे और

मध्यम व्यापारियों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने व्यापारियों के हक के लिए आवाज उठाई और बाजारों के विकास को प्राथमिकता दी। वकार चौधरी का लक्ष्य लक्ष्मी नगर में बेहतर सड़कें, साफ-सुथरी गलियां, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और रोशनी से जगमगाती गलियां तैयार करना है। वे मानते हैं कि असली विकास तभी होगा जब हर गली और हर मोहल्ले का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

लक्ष्मी नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी है, लेकिन अब तक यहां कोई मजबूत मुस्लिम नेतृत्व नहीं था। वकार चौधरी इस कमी को पूरा कर रहे हैं। वे केवल मुस्लिम समाज के नहीं, बल्कि पूरे बहुजन और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जो समाज के सभी वर्गों को न्याय और समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वकार चौधरी बसपा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ₹सबका विकास, समान अधिकार₹ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएँ हैं गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाना, स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना और क्षेत्र के हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना। लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर पहले सीधी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मानी जा रही थी। लेकिन वकार चौधरी के मैदान में उतरने के बाद समीकरण बदल गए हैं। दलित, पिछड़े, मुस्लिम और व्यापारी वर्ग से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि अब मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है और बसपा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है।

वकार चौधरी ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार एक सशक्त और ज़मीन से जुड़े हुए प्रत्याशी को जिताएं, जो हर समय उनके बीच रहकर उनके हक की लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा, मेरा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लक्ष्मी नगर के हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए और क्षेत्र का समुचित विकास हो, तो इस बार हाथी के निशान पर वोट दें। इस बार लक्ष्मी नगर में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है और जनता के समर्थन से वकार चौधरी की जीत के संकेत मजबूत होते जा रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कई अवसर गंवा दिए गए: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2025-26 पर टिप्पणी करते हुए जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि इसमें ₹कई अवसर गंवा दिए गए हैं। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में कटौती, छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब को समायोजित करने जैसे कई सकारात्मक पहलुओं की हम सराहना करते हैं, । इससे करदाताओं के हाथ में अधिक व्यय योग्य आय बचेगी तथा उपभोग एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी सकारात्मक बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के बावजूद, बजट में राजकोषीय विवेक बनाए रखा गया तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक सीमित रखा गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारा उधार नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा व्यावसायिक विनियमनों को सरल बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विनियामक सुधारों को आगे बढ़ाने से व्यवसाय को आसान बनाने में मदद मिलेगी तथा निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

जमाअत के अध्यक्ष ने आगे कहा, ₹हम कई मामलों में इस बजट से निराश हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति कम जीडीपी और कृषि विकास के साथ गंभीर आजीविका संकट के आधार पर वित्त मंत्री के लिए बजट में आमूलचूल नीतिगत बदलाव करने का एक अच्छा अवसर था ताकि असमानता, बेरोजगारी और उपेक्षित वर्गों की समस्या को दूर करने के लिए पुनर्वितरण न्याय, समान विकास और प्रभावी शासन को प्राथमिकता दी जा सके। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव सौंपे थे जिसमें व्यापार वृद्धि और कर प्रोत्साहन पर केंद्रित 'आपूर्ति' की रणनीति से हटकर नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि, उपभोग को प्रोत्साहन और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने के उद्देश्य से 'मांग' की रणनीति अपनाने की जोरदार वकालत की गई थी। दुर्भाग्य से, जब हमने बजट 2025-26 का अध्ययन किया तो हमें लगा कि हमारे अधिकांश सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता है कि बजट में कई अवसर चूक गए। केंद्रीय बजट 2025-26 को स्वाभाविक तौर से विस्तारवादी होना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत कुल व्यय में लगभग एक लाख करोड़ की कमी कर दी गई है। इसका सामाजिक व्यय पर प्रभाव पड़ना निश्चित है तथा गरीबों की दुर्दशा और भी अधिक बढ़ जाएगी।

सैयद सआदतुल्लाह ने कहा, ₹हमने मनरेगा में कटौती को वापस लेने, शहरी रोजगार योजना शुरू करने, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद के 6% आवंटन के साथ एक व्यापक शिक्षा मिशन शुरू करने की मांग की थी। इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, बजट में अल्पसंख्यकों के उत्थान, एससी/एसटी सशक्तिकरण या कृषि ऋण राहत पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है जिससे सामाजिक न्याय और समान विकास के प्रमुख मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं। हमने राजस्व के मामलों में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की अधिकतम सीमा 5% रखने, विलासिता कर लगाने, बड़ी कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने और केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का सुझाव दिया था। लेकिन, बजट इन महत्वपूर्ण उपायों पर चुप है। इसी प्रकार, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल कर, कर-मुक्त अवसंरचना बांड, तथा प्रभावी मानकों के साथ मजबूत सीएसआर मानदंडों को शामिल नहीं किया गया। इन सुधारों का अभाव से असमानता को दूर करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करने तथा वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। हमारा दृढ़ मत है कि सरकार को एक प्रगतिशील राजस्व नीति अपनाने की आवश्यकता है जो आम नागरिक को प्राथमिकता दे तथा समतामूलक विकास का समर्थन करे।

वर्तमान बजट पर अपनी प्रतिक्रिया के अंत में उन्होंने कहा, ₹जैसा कि बजट 2025-26 के अवलोकन से पता चलता है, व्यय का बड़ा हिस्सा (20%) ऋण पर ब्याज भुगतान की ओर जाता है। यह हमारे गैर-उत्पादक व्यय का एक बड़ा हिस्सा है जिसका उपयोग हम लोगों के कल्याण के लिए कर सकते थे। ऋण-जाल में फंसने से बचने के लिए हमें इक्विटी-आधारित वित्त मॉडल और ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर साहसिक कदम उठाना होगा। पारंपरिक बैंकों में इक्विटी-आधारित ब्याज-मुक्त बैंकिंग सुविधा को शामिल करके हम इस दिशा में शुरुआत कर सकते हैं। हमारी ओर से वित्त मंत्रालय को भी यह सुझाव दिया गया। यह एक अभिनव दृष्टिकोण होगा और हमें अपने राजनीतिक विचारों को गंभीर आर्थिक और ऋण-संबंधी चुनौतियों के लिए समय-परीक्षित समाधान तलाशने से नहीं रोकना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सरकार पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठेगी तथा बजट को आर्थिक नीति में वास्तविक परिवर्तन के साधन के रूप में रखेगी, जिससे देश के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचे।

दिल्ली का चुनाव भाजपा नहीं, बल्कि भाजपा के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है- मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता का भाजपा के गुंडे खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसकी शिकायत करने वाले लोगों पर ही दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। कालकाजी, जंगपुरा और राजेंद्र नगर विधानसभा में सोमवार की रात भाजपा के लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कालकाजी में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे भाजपा के लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय इनकी वीडियो बना रहे दो युवकों को पुलिस ने बड़ी बर्बरता से पीटा। साथ ही, इसकी शिकायत करने पर दिल्ली की सीएम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार को यह खुलासा वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, दिल्ली की सीएम आतिशी और दुर्गेश पाठक ने की।

उधर, इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का "काम" आम आदमी पार्टी के खिलाफ ख़ुद गुंडागर्दी करना, भाजपा की गुंडागर्दी को संरक्षण देना, दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें यह "काम" करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के "काम" में बाधा डालने का केस किया जाएगा।

तमाम वीडियो सबूत और शिकायत के बाद भी पुलिस व चुनाव आयोग गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है- मनीष सिसोदिया

वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे देश के चुनाव आयोग को पूरे देश में सराहा जाता था। इस चुनाव आयोग की अगुवाई कभी टीएन शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) जैसे लोगों ने की थी। जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था। निष्पक्ष चुनाव यानि टीएन शेषन। आज टीएन शेषन की कुर्सी पर राजीव कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव आयोग काम

कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा ने पूरा का पूरा चुनाव लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। दिल्ली में चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, बल्कि भाजपा के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है। जिस तरह पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियो दिख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। वहीं, पुलिस शिकायत करने के वाले लोगों व पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग उल्लंघन और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है, बल्कि चुनाव की घोषणा के पहले से ही हो रहा है।

महिला कार्यकर्ताओं को मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी जा रही है- मनीष सिसोदिया

झुग्गियों में लोगों को डराकर उनके वोटर कार्ड लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही- मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ पत्रकार झुग्गी में गए थे। वहां बच्चों ने कहा कि किस तरह से भाजपा के गुंडे आकर उन्हें धमकाकर जाते हैं कि खबरदार अगर तुमने झाड़ू पर वोट डाला तो तुम्हारी झुग्गियां बर्बाद कर देंगे। जगह-जगह कार्यकर्ताओं को धमकी देने का सिलसिला खुले में चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में कोई इनके पास कैसे जाएगा। जब जिस चीज के सबूत हैं, उसी पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे कई झुग्गियों से यह भी पता चला है कि ये लोगों को धमकाकर उनके वोटर कार्ड ले ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर वोट डालने गए। वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं।

अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो दिल्ली की सरकार माफिया चलाएंगे- मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र, सरकार बनाने और लोगों के लिए लड़ा जा रहा है या गुंडागिरी के लिए लड़ा जा रहा है? भाजपा जिस तरह से चुनाव आयोग और पुलिस का इस्तेमाल करके हरकतें कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल की जो बात है कि अगर गलती से भी भाजपा जीत गई तो सारी झुग्गियां तोड़ देगी। दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, फ्री बिजली-पानी, फ्री बस यात्रा और 24 घंटे जैसी सुविधा मिल रही है, इसके माफिया इन सब सुविधाओं को बर्बाद और खत्म कर देंगे। सारी योजनाएं खत्म कर देंगे। अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार नेता नहीं बल्कि माफिया चलाएंगे। एक और वीडियो आया है कि किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी और उनके गुंडे जंगपुरा में महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। सरेआम डंडा लेकर पीट रहे हैं। अगर भाजपा सरकार में आती है तो आगामी दिल्ली का वह नक्शा, वह झलक, वह नजारा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह का नजारा दिखेगा। जिस तरह का नजारा ये लोग अभी चुनाव लड़ते हुए दिखा रहे हैं।

भाजपा और चुनाव आयोग एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं- मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजीव कुमार ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर पर ला दिया है कि अब भाजपा और चुनाव आयोग एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। अपने आप को निष्पक्ष कहने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक मुद्दा उठाया गया कि भाजपा के कार्यकर्ता कालकाजी विधानसभा में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे। उनके मुद्दे मुख्यमंत्री आतिशी ने उठाए थे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता तब साबित होती अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देता। क्या चुनाव आयोग उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है, जिसने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर करके भाजपा के गुंडों के हौंसले बढ़ाए हैं? किस नियम के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर की गई। शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर की गई और गुंडागर्दी करने वालों को भगा दिया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो कार्रवाई करते दिखाए। चुनाव आयोग एक बयान जारी करने से नहीं, बल्कि अपनी हरकतों से निष्पक्ष होगा। आज वह अपनी हरकतों से भाजपा का एजेंट बना हुआ है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि *रमेश बिधूड़ी के लोग झुग्गी के लोगों को रात में धमका रहे थे, हमारी शिकायत पर पुलिस उन्हें ले गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी रमेश बिधूड़ी के लोग झुग्गियों में घूम रहे रहे थे, उनकी फोटो भी है।

गोविंदपुरी के एसएचओ ने कार्रवाई करने के बजाय रमेश बिधूड़ी के लोगों को भगा दिया।

चुनाव आयोग शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ ही केस कर रहा है। दिल्ली की जनता सब देख रही है, बहुत सोच-समझ कर अपना फैसला लेगी।

दुर्गेश पाठक ने बताया कि कार में पैसे व शॉल लेकर बैठे भाजपा कार्यकर्ता पर कार्रवाई के बजाय पुलिस ने शिकायत करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज की। पूरी दिल्ली में पैसे, साड़ियां और शॉल बांटी जा रही है और चुनाव आयोग खामोश है।पांच फरवरी का दिन भारत के चुनावी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि उसके खिलाफ वोट देने वाले लोग पोलिंग बूथ तक न पहुंचे।

विश्व कैंसर दिवस पर सफदरजंग अस्पताल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। विश्व कैंसर दिवस दुनिया भर के लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल एक महत्वपूर्ण दिन होता है। कैंसर अब एक महामारी बन चुका है और भारत और पूरी दुनिया में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले भारत में ही 15 लाख नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सबसे ऊपर हैं। लगभग 2 लाख महिलाओं में स्तन और 1.25 लाख महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का निदान किया गया है। दोनों कैंसर स्वस्थ जीवन शैली, धूम्रपान, शराब, तंबाकू चबाने, गुटखा, सुरक्षित यौन व्यवहार से बचने और एक से अधिक भागीदारों से बचने से रोके जा सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए टीकाकरण उपलब्ध है जो सर्वोत्तम एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लिए 9-14 वर्ष के बीच दिया जाता है और कैंसर को रोकने में एक लंबा रास्ता तय करता है। स्तन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच स्तन के लिए मैमोग्राम द्वारा उपलब्ध है; गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए पैप, एचपीवी और वीआईए। स्क्रीनिंग टेस्ट 25-65 वर्ष के बीच साल में 3 बार किया जाना चाहिए, भले ही कोई लक्षण न हों। स्क्रीनिंग से गर्भाशय ग्रीवा की परत में परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है जिसे सरल तरीकों से पता लगाया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में अधिकांश स्क्रीनिंग टेस्ट निःशुल्क हैं।

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने कैंसर की जांच और शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अपने ओपीडी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन चिकित्सा अधीक्षक डॉ संदीप बंसल, वीएमएमसी की प्रिंसिपल डॉ गीतिका खन्ना ने एचओडी ओबीजीएन डॉ बिंदु बजाज, सभी अतिरिक्त एमएस - डॉ आरपी अरोड़ा, डॉ रेखा तिर्की, डॉ चारू, डॉ सरिता शमसुंदर प्रभारी स्त्री रोग की उपस्थिति में किया। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया -

कैंसर की जांच और रोकथाम के महत्व पर एमबीबीएस छात्रों द्वारा एक जीवंत नुक्कड़ नाटक और एमबीबीएस छात्रों द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कैंसर से बचे लोगों ने अपने अनुभवों और कैंसर के इलाज के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार के अनुपालन के महत्व के बारे में बात की।

नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को मिलेगी पेड लीव, 5 फरवरी के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी सभी 70 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। इसको देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में सेवारत दिल्ली के मतदाताओं को पेड लीव मिलेगी। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में अनुमति पत्र जारी किया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कर्मचारी पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में सेवारत दिल्ली के मतदाताओं का बुधवार यानी पांच फरवरी को सवेतन अवकाश मिलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अनुमति पत्र जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।

मतदान के चलते दिल्ली के जो मतदाता जिले में कार्यरत हैं, वह अपने माताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत करने में सहभागिता निभाएं।

बताया जनपद में विभिन्न कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मियों का सवेतन अवकाश रहेगा। बताया आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में भी मतदान के लिए छुट्टी घोषित

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर पांच फरवरी बुधवार को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकारी महकमों, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित तमाम दफ्तरों में कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। ताकि कर्मचारी मतदान कर सकें।

आज मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में पहुंच रही ईवीएम

दिल्ली के मतदान केंद्रों पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में ईवीएम पहुंच रही हैं। पूर्वी दिल्ली के आइटीआई नंद नगरी व खेलगांव में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। ईवीएम वितरण केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन कार्यालय ने प्लान बनाया है। तीन चरणों में ईवीएम बांटी जाएंगी। तीनों चरणों में एक से दो घंटे का अंतराल रहेगा।

बसों के जरिये ईवीएम मतदान केंद्रों पर जाएंगी। जाम न लगे इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ईवीएम केंद्रों के पास मोर्चा संभालेगी। पूर्वी जिला निर्वाचन अधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि छह विधानसभा क्षेत्र हैं। 186 मतदान केंद्र व 1020 पोलिंग स्टेशन हैं। मंगलवार सुबह से ईवीएम का वितरण शुरू होगा। वितरण में काफी भीड़ हो जाती है।

तीन चरणों में होगा EVM का वितरण

इस बार भीड़ को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तीन चरणों में वितरण होगा। 121 बसों से ईवीएम जाएंगी। इतनी बसें एक साथ सड़क पर खड़ी होंगी तो जाम लग जाएगा, इसलिए तीन चरण बनाएं गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में ईवीएम केंद्रों पर जाएंगी। उत्तर पूर्वी जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ बनाया गया है। यहां महिलाएं कमान संभालेंगी।

उन्होंने कहा कि पूरे जिले में मतदान केंद्र तैयार हो गए हैं। सेल्फी पाइंट भी बनाएं गए हैं। केंद्रों पर वालंटियर भी रहेंगे, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर भी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।

खत्म हुआ चुनावी शोर, अब मतदान बढ़ाने पर पूरा जोर

18 जनवरी से गली-मोहल्लों में चल रहे चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया है। अंतिम दिन सभी दलों के उम्मीदवारों ने रोड शो के माध्यम से पांच बजे तक खूब प्रचार किया। इसके साथ ही प्रशासन मतदान बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहा है।

उम्मीदवारों के बूथ एजेंट भी एक-एक वोट को संजोने के लिए पर्ची के साथ ईवीएम में से जुड़ा हैंडबिल भी दे रहे हैं। उधर विधानसभा वार तैनात किए गए बीएलओ मतदाता पर्चियां बांट रहे हैं। साथ ही मतदाताओं को हेल्प लाइन के बारे में भी बताया जा रहा है। बूथ का पता करने को लेकर भी लोकेशन संबंधी लिंक भेजा जा रहा है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का बेहतरीन मौका, आवासीय भूखंड की एक और योजना निकालेगा यीडा

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) एक बार फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लोगों को बसने का मौका देने जा रहा है। मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टर 15 सी में आवासीय भूखंड योजना निकाली जाएगी।

प्राधिकरण ने भूखंड योजना के रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। चालू वित्त वर्ष में भूखंड योजना आने से आवेदकों को मौजूदा दर पर भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा।

803 आवासीय भूखंडों का आवंटन

यमुना प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में 803 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया है। आरपीएस 08 में 352 व आरपीएस 08 ए में 452 आवासीय भूखंडों का सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22 डी व 24 ए में आवंटन किया गया है।

मास्टर प्लान 2021 में नियोजित आवासीय सेक्टरों में उपलब्ध लगभग सभी भूखंडों के आवंटन के बाद प्राधिकरण की लिए नई आवासीय भूखंड निकालने की चुनौती बढ़ गई थी।

ताकि लोगों को आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए भूखंड मिलने के साथ प्राधिकरण की झोली भी राजस्व से भरी जा सके। चालू वित्त वर्ष में आवासीय श्रेणी से ढाई हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टर 15 सी में आवासीय भूखंड योजना निकालने का निर्णय लिया है।

रेरा पंजीकरण होते ही भूखंड योजना कर दी जाएगी लॉन्च

प्राधिकरण के पास पहले ही इस सेक्टर की 180 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। मास्टर प्लान में शामिल करने से पहले इसका उपयोग हरित था, लेकिन मास्टर प्लान में शामिल होने के बाद इसका उपयोग आवासीय कर दिया है। इसके अतिरिक्त 80 हेक्टेयर जमीन सरकारी है।

इसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव भी प्राधिकरण की ओर से मंडलायुक्त को भेजा गया है। मंडलायुक्त की स्वीकृति के बाद जमीन प्राधिकरण के नाम दर्ज कर उस पर भी भूखंड नियोजित किए जाएंगे।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि रेरा पंजीकरण होते ही भूखंड योजना लॉन्च कर दी जाएगी। इसी माह भूखंड योजना लांच होने की संभावना है।

मौजूदा दर पर भूखंड खरीदने का मिलेगा मौका

आवासीय श्रेणी के लिए प्राधिकरण की भूखंड दर 25900 रुपये प्रति वर्गमीटर है। आगामी वित्त वर्ष में प्राधिकरण की संपत्ति दरों में वृद्धि होना तय है। चालू वित्त वर्ष में भूखंड योजना आने से लोगों को मौजूदा दर पर भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा।

गाजियाबाद में जी.डी.ए का ताबड़तोड़ एक्शन, कई तैयार फ्लैट तोड़े; कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

अवैध निर्माण के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की कार्रवाई जारी है। दुहाई में अवैध रूप से निर्मित चार मंजिला इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। इस इमारत में 40 फ्लैट थे जिनमें से कुछ तैयार थे और कुछ निर्माणाधीन थे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर और पोकलेन मशीन से इमारत को ध्वस्त किया और फिर कामगारों ने हथौड़ों से इमारत को तोड़ा।

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम ने सोमवार को भी दुहाई स्थित चार मंजिला इमारत में निर्माणाधीन और तैयार फ्लैट का ध्वस्तीकरण जारी रखा। इनमें चार ब्लॉक तैयार फ्लैट के भी हैं, जिन पर बुलडोजर व पोकलेन मशीन के बाद जीडीए की ओर से कामगारों के हथौड़ों से वार किया जा रहा है।

इमारत में बने थे 40 फ्लैट

करीब तीन हजार वर्ग मीटर में अवैध रूप से तैयार 40 फ्लैट की चार मंजिला इमारत पर जीडीए की प्रवर्तन इकाई बुलडोजर और पोकलेन मशीन से ध्वस्तीकरण में लगी है। बिल्डर की ओर से लोगों को सब्जी बाग दिखाकर फ्लैट 30 से 35 लाख रुपये की बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिनमें से करीब आधा दर्जन फ्लैट की रजिस्ट्री की तैयारी थी।

बुलडोजर और हथौड़े से किया गया ध्वस्तीकरण

रविवार को चार फ्लैट के एक ब्लॉक को ध्वस्त करने के साथ ही दो अन्य ब्लाक में ध्वस्तीकरण किया गया था। तीसरे दिन भी जीडीए ने कार्रवाई को जारी रखा।

मौके पर मौजूद पुलिसबल के साथ प्रवर्तन दल प्रभारी अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता की मौजूदगी इमारत के तैयार चार ब्लॉक पर बुलडोजर और हथौड़े से ध्वस्तीकरण किया गया। अधिशासी अभियंता पियूष सिंह ने बताया कि इमारत में बने सभी ब्लाक को ध्वस्त किया जाएगा।

डूंडाहेड़ा में 200 करोड़ की जमीन कराई कब्जामुक्त

उधर, एक अलग मामले में क्रॉसिंग रिपब्लिक डूंडाहेड़ा में निगम की 40 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है। सोमवार को चलाए गए अभियान में मौके पर संपत्ति प्रभारी पल्लवी सिंह और संपत्ति अधीक्षक रामशंकर के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।

अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर निगम की भूमि को कब्जामुक्त कराया जा रहा है। डूंडाहेड़ा ग्राम में भी अभियान चलाया गया और खसरा नंबर 122,123,129,304, 305, 306/7, 307 308 को कब्जामुक्त कराया गया। कब्जा करने वालों ने भूमि पर अपने पट्टे बताए।

इन पट्टे को एसडीएम द्वारा भी निरस्त किया जा चुका है। हाईकोर्ट में भी कब्जा करने वालों की हार हो चुकी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने निगम की रिक्त भूमि को इसी प्रकार अभियान चलाते हुए कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि रिक्त भूमि शहर हित में ही इस्तेमाल में ली जाएगी, जिसका निर्णय सदन द्वारा लिया जाएगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे का ज्वाइंट एक्सपेंशन टूटा, दो लेन पर बंद रहेगी यातायात

द्वारका एक्सप्रेसवे का एक ज्वाइंट एक्सपेंशन बजघेड़ा के पास टूट गया है। एक्सप्रेसवे को मजबूत बनाने के लिए हर कुछ मीटर पर करीब 14 मीटर का जॉइंट एक्सपेंशन बिछाया गया है। हालांकि जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच से यह भी पता चलेगा कि ज्वाइंट विस्तार की गुणवत्ता से समझौता किया गया था या नहीं। जांच भोपाल की एक विशेषज्ञ कंपनी द्वारा की जा रही है।

गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक ज्वाइंट एक्सपेंशन बजघेड़ा के पास टूट गया है। शनिवार को एक डंपर ज्वाइंट एक्सपेंशन (लोहे की ग्रिल) के ठीक ऊपर आगे चल रही कार से टकरा गया।

ज्वाइंट एक्सपेंशन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन मामले की जांच पूरी होने तक एक्सप्रेसवे पर करीब 50 मीटर तक यातायात बंद रहेगा। वाहनों का ज्यादा दबाव न होने से कोई दिक्कत नहीं है।

14 मीटर का जॉइंट एक्सपेंशन बिछाया

एक्सप्रेसवे को मजबूत बनाने के लिए हर कुछ मीटर पर करीब 14 मीटर का जॉइंट एक्सपेंशन बिछाया गया है। इसके ऊपर कंक्रीट डाली गई है, जिससे यह दिखाई नहीं देता। अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार को डंपर चालक ने दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी।

जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी

इससे नीचे के ज्वाइंट विस्तार पर काफी दबाव पड़ता। हालांकि, जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच से यह भी पता चलेगा कि ज्वाइंट विस्तार की गुणवत्ता से समझौता किया गया था या नहीं। जांच भोपाल की एक विशेषज्ञ कंपनी द्वारा की जा रही है।

बारीकी से जांच की जा रही

प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में यदि ज्वाइंट एक्सपेंशन को बदलने का सुझाव आया तो बदल दिय जाएगा। फिलहाल जहां पर टूटा है उसे ठीक किया जा रहा है।

गुणवत्ता के साथ समझौता

गांव दौलताबाद निवासी राजकुमार कहते हैं कि कार में डंपर की टक्कर मात्र से ही जब ज्वाइंट एक्पेंशन टूट गया फिर यदि डंपर पलट जास तो क्या होगा। निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है।

बता दें कि निर्माण के दौरान गांव दौलताबाद के सामने द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। उस समय भी निर्माण में गुणवत्ता के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। दिल्ली इलाके में भी महिपालपुर के नजदीक एक हिस्सा टूटकर गिर गया था।

एनएचएआइ द्वारा गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। गुरुग्राम इलाके में निर्माण की जिम्मेदारी एलएंडटी नामक कंपनी के पास थी। फिलहाल मेंटिनेंस की जिम्मेदारी है। गुरुग्राम भाग चालू हो चुका है, दिल्ली भाग आधा-अधूरा चालू होना है।

हीरो होंडा चौक की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं

हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर का जयपुर-दिल्ली भाग लगभग 200 मीटर तक बंद है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। छह महीने पहले बना एक गड्ढा ठीक भी नहीं हुआ था कि एक महीने पहले एक और गड्ढा बन गया। मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है।

फ्लाईओवर के निर्माण में लापरवाही

फ्लाईओवर के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। केवल निर्माण कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा।

नोएडा एयरपोर्ट से कब शुरू होगी टिकट बुकिंग की सुविधा? आ गया बड़ा अपडेट

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद टिकट की बिक्री शुरू होगी। विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. तीन जनवरी को लाइसेंस के लिए डीजीसीए के यहां आवेदन कर चुकी है। डीजीसीए ने 17 फरवरी तक आपत्ति निस्तारण का समय दिया है।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री केआर नायडू ने अप्रैल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) से विमान सेवा की घोषणा की है। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

अब तक 9024.12 करोड़ रुपये हो चुके खर्च

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह बुधवार को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण प्रगति का भी जायजा लेंगे।

एयरपोर्ट का 77.77 प्रतिशत कार्य पूरा होने के साथ निर्माण पर अब तक 9024.12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। रनवे, एटीसी का काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग में आंतरिक साज सज्जा आदि का काम जारी है।

मार्च अंत तक एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने की संभावना

लेकिन एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग का मौका एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद ही मिलेगा। मार्च अंत तक एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने की संभावना है।

इसके लिए तीन फरवरी को आवेदन किया जा चुका है। डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए तीन जनवरी को आवेदन किया गया है। डीजीसीए ने आपत्ति दर्ज कराते हुए 17 फरवरी तक निस्तार का समय दिया है। आपत्ति निस्तारण के बाद एयरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति से तय होगी उद्घाटन की तिथि

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) करेंगे। एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति से एयरपोर्ट की उद्घाटन की तिथि तय होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट

भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। हाल ही के समय में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में व्यक्तिगत आयकर की भागीदारी कारपोरेट क्षेत्र से आयकर की भागीदारी से भी अधिक हो गई है।

दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। सीतारमन ने एक महिला वित्तमंत्री के रूप में लगातार 8वां बजट लोकसभा में पेश कर एक रिकार्ड बनाया है। वित्तमंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया बजट अपने आप में पथप्रदर्शक, अग्रणी एवं अतुलनीय बजट कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय से देश की अर्थव्यस्था में विकास की गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी अतः विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के हाथों में अधिक धनराशि शेष बच सके ताकि वे विभिन्न उत्पादों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में इनकी मांग बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। साथ ही, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश, निर्यात एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन्हें विकास के इंजिन के रूप में विकसित किया जा सके।

भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। हाल ही के समय में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में व्यक्तिगत आयकर की भागीदारी कारपोरेट क्षेत्र से आयकर की भागीदारी से भी अधिक हो गई है। अतः मोदी सरकार से अब यह अपेक्षा की जा रही थी कि मध्यमवर्गीय परिवारों को बजट के माध्यम से कुछ राहत दी जाय। और फिर, मुद्रा स्फीति की सबसे अधिक मार भी गरीब वर्ग के परिवारों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर ही पड़ती दिखाई देती है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर की वर्तमान सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अर्थात अब 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा। वेतन एवं पेंशन पाने वाले नागरिकों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती की राहत इसके अतिरिक्त प्राप्त होगी। इस वर्ग के करदाताओं को 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही, आय कर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 4 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर शून्य रहेगी। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर 5 प्रतिशत, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर 25 प्रतिशत एवं 24 लाख रुपए से अधिक की कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा।

मध्यमवर्गीय करदाताओं को उक्त सुधारों से लगभग 80,000 रुपए से 1.10 लाख रुपए तक की राशि की बचत होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस सुधार से कुल मिलाकर देश के बजट में एक लाख करोड़ रुपए की राशि कम प्राप्त होगी अर्थात मध्यमवर्गीय परिवारों को कुल एक लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का लाभ होगा। और, यह लाभ लगभग 2 करोड़ करदाताओं को होने की सम्भावना है। इससे देश के मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों के हाथों अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी जिसे वे विभिन्न उत्पादों की खरीद पर खर्च करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होंगे। मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों ने जितना सोचा था शायद उससे भी कहीं अधिक राहत उन्हें इस बजट के मध्यम से दी गई है। इसीलिए ही, इस बजट को अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट की संज्ञा दी जा रही है।

मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों को, आयकर में छूट देकर, दी गई राहत देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे बजटीय घाटा में वृद्धि नहीं हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना पूर्व में की गई थी, परंतु अब संशोधित अनुमान के अनुसार यह बजटीय घाटा कम होकर 5.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय घाटा 5.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। अतः देश की वित्तीय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हां, पूंजीगत खर्चों में जरूर कुछ कमी रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च के अनुमान के विरुद्ध 10.18 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था बजट में की गई है। इस राशि को 11.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए किया जाना चाहिए था क्योंकि पूंजीगत खर्च में वृद्धि से देश में आर्थिक विकास की दर तेज होती है और रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में एक रास्ता यह निकाला गया है कि केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये संस्थान भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करें ताकि उनके द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों की राशि को मिलाकर कुल पूंजीगत खर्च को 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाया जाए।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि धन धान्य योजना को 100 जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से इन जिलों में ली जा रही फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दलहन के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं स्टार्टअप के लिए ऋण की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा रहा है। लेदर उद्योग में रोजगार के 22 लाख नए अवसर निर्मित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खिलौना उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाया जाएगा। आज भारत खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करता है अतः तलहन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।। भारत में निर्मित विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों की तलाश करते हुए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सम्पन्न किए जा रहे हैं। देश में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है। विभिन्न शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया जा रहा है।

युवाओं में कौशल विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, आगामी 5 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 युवाओं को अतिरिक्त दाखिला दिए जाएंगे। इंडियन इन्स्टिटूट आफ टेक्नॉलजी कॉलेजों में टेक्नलाजिकल रीसर्च के लिए 10,000 पी एम स्कालर्शिप प्रदान की जाएंगी एवं नए आईआईटी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आरटीफिशियल इंटेलीजेंस सेंटर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

श्री अयोध्या धाम, महाकुम्भ क्षेत्र प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा ताकि देश में धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। देश में 52 नए पर्यटन केंद्र भी विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है तथा भगवान बुध सर्किट भी विकसित किया जाएगा।

- प्रहलाद सबनानी

एमजी ग्लोस्टर और हेक्टर के बाद कॉमेट ईवी को मिल सकता है ब्लैकस्टॉर्म संस्करण, एक सटीरियर से लेकर इंटीरियर में होगा यह बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

एमजी धूमकेतु ईवी ब्लैकस्टॉर्म संस्करण ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG मोटर्स की ओर से देश की सबसे सस्ती ईवी के तौर पर MG Comet EV को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस ईवी को नए एडिशन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे किस तरह के एडिशन के साथ लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट में ICE और EV तकनीक वाली कारों को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से जल्द ही EV सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती गाड़ी के तौर पर ऑफर की जाने वाली MG Comet EV को Blackstorm Edition के साथ लाया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसे कब तक लाया जा सकता है। किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Comet EV का आएगा Blackstorm Edition

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमजी की ओर से कॉमेट ईवी के ब्लैकस्टॉर्म एडिशन को भारतीय बाजार में लाया जा सकता है। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी को नहीं दिया गया है।

क्या होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से MG Comet EV Blackstorm Edition में जो बदलाव किए जाएंगे वह पूरी तरह से कॉस्मैटिक होंगे। इसकी बैटरी और मोटर के अलावा डिजाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें MG Gloster और Hector के Blackstorm Edition की तरह ही ब्लैक पेंट स्कीम के साथ रेड इंसर्ट्स को दिया जाएगा। इसी थीम को इंटीरियर में भी देखा जा सकेगा। ब्लैकस्टॉर्म एडिशन वाली गाड़ी में इसकी बैजिंग को भी दिया जाएगा।

बैटरी और मोटर

MG Comet EV में कंपनी की ओर से 17.3 kWh की क्षमता की बैटरी को ऑफर किया जाता है। जिसे फुल चार्ज करने के बाद 230 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से 41 बीएचपी की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कैसे हैं फीचर्स

MG Comet EV में कंपनी की ओर से कुछ बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें सफेद रंग के साथ सिल्वर फिनिश की को दिया जाता है। इसके साथ ही गाड़ी में ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिए जाते हैं। 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, 55 से ज्यादा कनेक्टिड कार फीचर्स, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, ईएसपी, ईपीबी, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितनी है कीमत

एमजी की ओर से कॉमेट ईवी को 6.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट को 9.83 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लाया जाता है। ऐसे में अगर इसके ब्लैकस्टॉर्म एडिशन को लाया जाता है तो इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है।

मेड इन इंडिया मारुति जिम्नी बनी जापानियों की पसंद, अस्थाई तौर पर रोकी गई बुकिंग, जानें कितना हुआ प्रतीक्षा अवधि

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति जिम्नी जापान इंतज़ार कर रही है भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई देशों में कई मॉडल स को एक सपोर्ट किया जाता है। कंपनी ने हाल में ही जापान में भी Jimny को ऑफर किया है। जहां इस मेड इन इंडिया एसयूवी को काफी ज यादा पसंद किया गया है। जापान में इस गाड़ी के लिए कितनी बुकिंग मिली हैं। कितना वेटिंग पीरियड हो गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की ओर से भारतीय बाजार के साथ ही कई देशों में अपने वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली Jimny को जापान में काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाड़ी के लिए कितनी बुकिंग मिल चुकी हैं और जापान (Maruti Jimny Japan) में इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जापानियों की पसंद बनी Maruti Jimny

मारुति की ओर से फाइव डोर ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Maruti Jimny को जापान में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कंपनी की इस एसयूवी को जापान में काफी ज्यादा बुकिंग भी मिल रही है।

कितनी यूनिट्स हुई बुक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की इस गाड़ी के लिए जापान में 50 हजार यूनिट्स की बुकिंग मिल चुकी हैं। खास बात यह है कि चार दिन पहले ही इस गाड़ी को जापान में लॉन्च किया गया है। बड़ी संख्या में बुकिंग मिलने के कारण एसयूवी की बुकिंग को अस्थाई तौर पर रोका गया है।

कितना हुआ वेटिंग पीरियड

जानकारी के मुताबिक जिम्नी की 1200 यूनिट्स को हर महीने जापान एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस स्थिति में मारुति की ओर से जापान के लिए हर साल 14400 यूनिट्स को ही भेजा जाएगा। ऐसे में 50 हजार बुकिंग मिलने के कारण वहां पर इस गाड़ी की डिलीवरी लेने में करीब 3.5 साल या 41 महीने तक का समय (Jimny Waiting Period in Japan) लग सकता है। हालांकि इस गाड़ी के पहले शिपमेंट को पहले ही जापान भेजा जा चुका है, ऐसे में वहां पर इसकी कुछ यूनिट्स को डिलीवरी के लिए उपलब्ध करवाया गया है।

अन्य देशों में भी होती है एक सपोर्ट

मारुति की ओर से जिम्नी को गुरुग्राम के प्लांट में बनाया जाता है। यहीं से इस गाड़ी को भारतीय बाजार के साथ ही कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत के अलावा इस गाड़ी के फाइव डोर वर्जन को लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट देशों में भेजा जाता है। फाइव डोर वर्जन के अलावा इसके थ्री डोर वर्जन को भी कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

कितनी है कीमत

जापानी बाजार में Jimny Nomade को 25.51 लाख जापानी येन से लेकर 27.50 लाख जापानी येन की कीमत पर ऑफर किया जाता है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 14.88 लाख रुपये से लेकर 15.43 लाख रुपये है। जापान में इसकी डिलीवरी को अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा।

वोक्सवैगन की कारों पर फ़रवरी 2025 में मिलेगा बड़ा डिस्काउंट, वर्टस, ताइगुन और टिग्वान पर बचेंगे लाखों रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। अगर आप कंपनी की किसी गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो कंपनी की ओर से अपनी कारों पर लाखों रुपये के (Volkswagen February 2025 Discounts Offers) ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी की किस गाड़ी और एसयूवी पर कितना Discount Offer किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारत में सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी इस महीने कंपनी की किसी गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो लाखों रुपये बचाने का मौका दिया जा रहा है। Volkswagen की किस गाड़ी पर इस महीने कितनी बचत की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Volkswagen Taigun पर कितना Discount Offer

कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर Taigun को ऑफर किया जाता है। Volkswagen Tiguan को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। February महीने में इस एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 2.2 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। यह बचत इसके 2024 में बनी हुई यूनिट्स पर दी जा रही है। इसके अलावा अगर आपको 2025 में बनाई गई यूनिट्स को खरीदना है तो कंपनी की ओर से इस महीने में अधिकतम 80 हजार रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Volkswagen Virtus पर कितना डिस्काउंट

फॉक्सवैगन भारत में इकलौती सेडान के तौर पर वर्टुस को लाती है। इसे मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस महीने इस सेडान पर भी 1.70 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। इससे पहले इस पर 1.50 लाख रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस महीने वर्टुस की 2024 की यूनिट्स पर यह डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको इसकी 2025 की यूनिट को खरीदना है तो 80 हजार रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Volkswagen Tiguan पर सबसे ज्यादा होगी बचत

Volkswagen की ओर से फ्लैगशिप एसयूवी के तौर पर Tiguan को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। अगर फेस्टिव सीजन के दौरान आप Tiguan को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कंपनी February 2025 में इस एसयूवी पर सबसे ज्यादा Discount Offer दे रही है। जानकारी के मुताबिक अगर इस एसयूवी को इस महीने में खरीदा जाता है तो कंपनी की ओर से 4.20 लाख रुपये तक के ऑफर्स को दिया जा रहा है।

क्या है शामिल

वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों पर कई तरह के डिस्काउंट्स को ऑफर किया जाता है। जिनमें कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस, स्क्रैपेज बोनस जैसे डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं।

ये 5 बाइक देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, एक लीटर पेट्रोल में तय कर सकेंगे 70km से अधिक का सफर

परिवहन विशेष न्यूज

हाई माइलेज मोटरसाइकिल हम यहां पर आपको ऐसी 5 मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं जो एक लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। वहीं इन मोटरसाइकिलों की कीमत भी एक लाख रुपये से कम है। इतना ही नहीं यह बाइक दमदार इंजन के साथ आती है। आइए इन माइलेज वाली बाइक के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। बजाज ने 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक Freedom 125 को लॉन्च किया। यह बाइक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल होने के साथ ही भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी बन गई है। कंपनी दावा कर रही है उनकी यह बाइक 330 किमी का ड्राइविंग रेंज देगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है।

1. Bajaj Freedom 125 CNG

कीमतः 95,000 रुपये से लेकर 1.10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)

माइलेजः 330km (पेट्रोल+CNG)

यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल है। Bajaj Freedom 125 CNG में 125cc सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकती है। इसमें लगा हुआ इंजन 9.5 PS की पावर और 9.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक शामिल किया गया है। यह तीन वेरिएंट में आती है। इसके NG04 ड्रम की एक्स-शोरूम कीमत 95 हजार रुपये, NG04 ड्रम LED की एक्स-शोरूम कीमत 1.05 लाख रुपए और NG04 डिस्क LED की एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपए है।

2. Honda Livo Drum

कीमतः 97,418.00 रुपये (एक्स-शोरूम)

माइलेजः 74 km

होंडा इस मोटरसाइकिल में 109.51 cc के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 8.79 PS की पावर और 9.30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी की तरफ से मोटरसाइकिल को लेकर दावा किया गया है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 74 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है।

3. Bajaj Platina 100

कीमतः 68,685 रुपये (एक्स-शोरूम)

माइलेजः 72km

बजाज ऑटो की यह एक पॉपुलर मोटरसाइकिल है, वो भी माइलेज को लेकर। इसमें 102 cc के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 7.79 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट जनरेट तकता है। कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल को लेकर दावा करती है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 72 किलोमीटर तक का माइलेज देती है।

4. Hero Splendor Plus

कीमतः 77,176 रुपये (एक्स-शोरूम)

माइलेजः 72km

हीरो मोटोकॉर्प की यह बाइक भारत में सबसे पॉपुलर होने के साथ ही सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल भी है। इसमें 97.2 cc इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो .02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि उनकी यह बाइक एक लीटर पेट्रोल पर 73 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है।

5. TVS Sport

कीमतः 59 881 रुपये से लेकर 71,223 रुपये तक (एक्स-शोरूम)

माइलेजः 70 km

टीवीएस मोटर की यह मोटरसाइकिल दो मॉडल में आती है। इसके मॉडल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 59,881 रुपये और दूसरे की कीमत 71,223 रुपये है। इसमें 109.7 cc का इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 8.19 bhp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि उनकी यह मोटरसाइकिल एक लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है।

आयकर छूट की सीमा बढ़ने से दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद

परिवहन विशेष न्यूज

जेफरीज का अनुमान है कि कर लाभ से लगभग 3.5 करोड़ करदाता को फायदा पहुंचेगा और प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 30 हजार रुपये का वार्षिक लाभ होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 43 लाख यात्री वाहन और 2.1 करोड़ दोपहिया वाहन के अनुमानित बाजार आकार को देखते हुए कर कटौती से अतिरिक्त खर्च में वृद्धि हो सकती है।

नई दिल्ली। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से दोपहिया और यात्री वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रस्तावित कर राहत से भारतीय मध्यम वर्ग को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कुल कर लाभ मिलेगा, जिसे आटोमोबाइल सहित विवेकाधीन खर्च में वृद्धि हो सकती है।

लगभग 30 हजार रुपये का वार्षिक लाभ होगा

जेफरीज का अनुमान है कि कर लाभ से लगभग 3.5 करोड़ करदाता को फायदा पहुंचेगा और प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 30 हजार रुपये का वार्षिक लाभ होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 43 लाख यात्री वाहन और 2.1 करोड़ दोपहिया वाहन के अनुमानित बाजार आकार को देखते हुए कर कटौती से अतिरिक्त खर्च में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आगामी वेतन वृद्धि आटो क्षेत्र को अतिरिक्त बढ़ावा दे सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है।

दोपहिया उद्योग में होगी वृद्धि

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दोपहिया और यात्री वाहन बढ़े हुए उपभोक्ता खर्च के सबसे बड़े लाभार्थियों में से होंगे। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 तक दोपहिया उद्योग के लिए 13 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान बरकरार रखा गया है। खास बात यह है कि जहां दोपहिया और यात्री वाहन खंडों में मजबूती से वृद्धि होने की उम्मीद है, वहीं ट्रक उद्योग के लिए 2ष्टिकोण कम आशावादी है। रिपोर्ट का मानना है कि धीमी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वृद्धि ट्रक की मांग को नुकसान पहुंचा सकती है।

सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

वित्त वर्ष 2025-2026 के यूनियन बजट को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेक्ट्रिक कारों की कीमतों को कम करने की बात की। इसके साथ ही लिथियम ऑयन बैटरी पर लगने वाले टैक्स को कम करने की बात भी कही थी। जिसके बाद से ही अब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

भूमि को विनाश से बचाने

विजय गर्ग

मुझे एक कार खरीदने की इच्छा है और अब जब मैं अब बाहर जाता हूं, तो मैं बाहर जाता हूं जब मैं बाहर जाता हूं। मैं वॉकिंग स्थल का शौकिया हूं और यह देखना एक अच्छी समझ है कि क्या मुझे इस सरल कदम के साथ कार्बन गैसों में कोई वृद्धि नहीं है, और इस सामान्य आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए मेरा एक छोटा योगदान भी है। आखिरकार, कई लोगों को मेरे लिए एक रास्ता माना जाता है। अंत में, ऐसा लगता हैहमारे सभी राजमार्गों के रूप में, लेट रुपये कारों, मोटरबेक और अन्य वाहनों के लिए बनाए जाते हैं। शांति से चलने या सड़क पार करने के लिए सड़क पर चलने के लिए कोई हरि नहीं है। इस विरोधाभास को देखें: यदि आप कार्बन गैसों की निकासी को कम करने में थोड़ा योगदान देना चाहते हैं, तो आप काम के नहीं हैं! हालांकि, वैज्ञानिकों को बार -बार दुनिया के लिए संदर्भित किया जाता है, दुनिया को दुनिया के लिए उठाया गया है, लेकिन हम पेड़ों को काट देंगे, मैगएक्सप्रेसवार एक बा को कारचिंग कारों, तालू, और शहरों के लिए एक बेकिंग, और शहरों के शहरों के डिजाइन के लिए एक बेकिंग है कि पैदल यात्री या साइकिल चलाना लगभग असंभव है। दिल्ली में 2023 फिगर बुकलेट डरावनी तस्वीर प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजधानी में, कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1,0 लाख थी, जिनमें से 33.8 प्रतिशत वाहन निजी थे। यह खेल तब भी समाप्त नहीं होता है, भले ही दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण का कुल प्रदूषण 38 प्रतिशत हो। ये सभी अभ्यासआपका फुटवियर सो रहा है। उदाहरण बंगलौर की कल्पना करें। बैंगलोर एक शांतिपूर्ण शहर था जो कुख्यात यातायात बनाकर एक शिगरिला क्षेत्र बन गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में 23 लाख निजी कारें हैं और लोगों को दस मील [10 किमी यात्रा यात्रा की यात्रा को कवर करने के लिए औसतन 30 मिनट का समय लगता है! हम एक कार में फंस गए हैं: अधिक कारें, उच्च यातायात, अन्य फ्लाईओवर, अन्य फ्लाईओवर, अधिक सटीक। फिर भी तकनीकी-पूंजीवाद, ठेकेदार और राजनेता जल्द ही एक और एक्सप्रेसवेउद्घाटन में उद्घाटन की गुणवत्ता करते रहें। 264 किमी लंबी दिल्ली-डेहरादुन एक्सप्रेसवे के रूप में आपको दो की अवधि की दूरी पर एक और शहर दूसरे को देगा। जैसा कि अक्सर होता है, हम एक फैंसी कार का एक नया मॉडल खरीदना चाहेंगे और अपने समय की गति की वृद्धि का एहसास करना चाहेंगे। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुद्दे को 7555 पेड़ों से काटने के लिए बहुत आराम के बारे में भूल जाएंगेले जाया गया! पेड़ों का पेड़ क्या है? इसी तरह विकास की आधुनिक परियोजना में छिपी हुई गति और परिवहन के आकर्षण ने भारत में भारत में भारत में भारी वृद्धि की है; 2024 में, यह आंकड़ा रु। 15 मिलियन यात्रियों को पार करने की उम्मीद है। प्रगति की प्रगति को सुनते हुए, हम यह दोषी नहीं ठहराते हैं कि हवाई यात्रा ऐसी गतिविधि है जो कार्बन गैसों को खाली करके सबसे अधिक प्रदूषण का कारण बनती है। लगता है, हम कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। हमअपने पड़ोसी को बनाए रखने और अपने बीपी और मधुमेह को बढ़ाते हुए, सुगंधित एरिंगर्स में मतदान में मतदान करता है। गति और परिवहन की यह मजदूरी जो अब एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों को व्यक्त नहीं करती है। इसके बजाय, मैं 'धीमी कीट' की लय हूं। गति के लिए हमारे फ्लेल का एक और निष्कर्ष उपभोक्तावाद की महिमा है। 'एक खरीदें, खरीदारी और अलर्ट के लिए मंडी मैनकोल के साथ एक मुफ्त प्राप्त करें, फिरएक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी फैंसी कपड़ों, आलू के चिप्स, या अलग पाउडर या एक नए स्मार्टफोन का एक पैकेट है। अक्ष की यह प्रवृत्ति पर्यावरण को अधिक कवर करती है। ये उपकरण जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, उन्हें चलाने की आवश्यकता होती है और फिर इसके परिवहन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कार्बन गैसों को बाहर लाता है। इस तरह, कपड़े का उत्पादन लाखों कचरे का कारण बनता है और बहुत छोटे कपड़े को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि-as-as ई-कॉमर्स ने बॉक्स बंद पदार्थों पर हमारी निर्भरता को बधाई दी है, प्लास्टिक में लिपटे बड़ी संख्या में पैकेज बड़ी संख्या में साझा कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्लास्टिक की एलिविटी हानिकारक रसायनों को लाती है जो कैंसर और अन्य शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कुछ धातुएं हैं जो अंततः बकवास खंभों के लिए रोमांचित हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक के कचरे के समुद्र में फेंकने की संभावना है जो गंभीर क्षति से प्रेरित होती हैहै। फिर भी पूंजीवाद का सिद्धांत हमें अधिक खरीदने के लिए रहता है, अन्य डिंगर के लिए, और यह पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जब आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो विशेष 'ऑफ़र और छूट' संदेश प्राप्त होते हैं और एक सामूहिक मनोरंजन माना जाता है, आदमी को पता चलता है कि उपभोक्ता सबसे पसंदीदा धर्म बन गया है। फिर भी, मुझे लगता है कि कम से कम एक जीवित है। मुझे पता है कि मेरी 'बेटी जीवन' या 'एक जीवित दृष्टिकोण नहीं है' आसपास हो रहा है: यह कोई फर्क नहीं पड़ता: जलवायु आपदा के विनाशकारी लक्षण। हमें संरचनात्मक परिवर्तनों के एक बहुत बड़े स्तर के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की कोशिश करने की आवश्यकता है, जिसके लिए दुनिया के नेताओं, नीति की कीमतों, नीति की कीमतों और कॉर्पोरेट श्रेणियों के लिए ऐतिहासिक परगना समझौता हैवैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विकास और आर्थिक प्रगति के तरीकों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और पुनर्जीवित करना होगा, लेकिन कार्बन उत्सर्जन के कारण कोई भी महान क्रांति नहीं हो सकती है, जहां तक आपने अपनी जीवनशैली को कम करने के लिए नहीं बदला है, इस पर दबाव न डालें सरकार और उनकी भूमि को विनाश से बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की आवश्यकता

विजय गर्ग

उद्योगों में एआई को बढ़ाने के कारण भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शिक्षा की बढ़ती मांग देखी है। भारत में विशेष एआई विश्वविद्यालयों की स्थापना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

1। स्किल गैप को संबोधित करते हुए एआई स्वास्थ्य सेवा, वित्त और विनिर्माण जैसे उद्योगों को बदल रहा है, लेकिन कुशल पेशेवरों की कमी है। एक समर्पित एआई विश्वविद्यालय उद्योग के लिए तैयार प्रतिभा का उत्पादन कर सकता है।

2। अनुसंधान और नवाचार भारत को स्थानीय चुनौतियों के लिए स्वदेशी एआई समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। एक विशेष एआई विश्वविद्यालय प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), कंप्यूटर दृष्टि और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

3। वैश्विक प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन जैसे देशों ने एआई में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एआई को समर्पित एक विश्वविद्यालय भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अंतरराष्ट्रीय एआई अनुसंधान में योगदान करने में मदद करेगा।

4। एआई फॉर सोशल गुड एआई भारतीय-विशिष्ट मुद्दों जैसे कृषि उत्पादकता में सुधार, चिकित्सा निदान को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को अनुकूलित करने को संबोधित कर सकता है। एक केंद्रित एआई विश्वविद्यालय ऐसे समाधान चला सकता है।

5। स्टार्टअप और उद्यमिता विकास भारत में एक तेजी से एआई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। एक समर्पित एआई विश्वविद्यालय इनक्यूबेटर, मेंटरशिप और फंडिंग के अवसरों के साथ स्टार्टअप का समर्थन कर सकता है।

6। सरकार और उद्योग सहयोग एआई में विशेषज्ञता रखने वाला विश्वविद्यालय शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच की खाई को पाट सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि एआई विकास राष्ट्रीय हितों और नीतियों के साथ संरेखित हो।

भारत में मौजूदा एआई शिक्षा जबकि भारत में अभी तक एक स्टैंडअलोन एआई विश्वविद्यालय नहीं है, कई संस्थान एआई-केंद्रित कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

आईआईटी (आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आदि) - एआई और डेटा साइंस प्रोग्राम आईआईटी हैदराबाद - सेंटर फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर - ऐआई & रोबोटिक्स अनुसंधान प्लाक्षा विश्वविद्यालय और अशोक विश्वविद्यालय - एआई और एमएल पाठ्यक्रम एमिटी, एसआरएम और मणिपाल जैसे निजी विश्वविद्यालय भी एआई कार्यक्रम प्रदान करते हैं निष्कर्ष तेजी से एआई विकास को देखते हुए, भारत को एक समर्पित एआई विश्वविद्यालय से लाभ होगा जो शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को एकीकृत करता है। सरकारी और निजी क्षेत्र को एआई क्रांति में भारत के नेतृत्व को सुनिश्चित करते हुए ऐसी संस्था स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

मानसिक रोग का बढ़ता दायरा

विजय गर्ग

आजकल की भाग-दौड़ वाली दुनिया में बेचैनी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। इससे न तो कोई देश बचा है और न ही कोई राज्य । इसका शिकार किशोर, बड़े, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं। विशेष रूप से, किशोरों में यह समस्या कुछ ज्यादा ही जटिल होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की 'मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल' नामक ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 10 से 19 वर्ष का प्रायः प्रत्येक सातवां किशोर किसी-न-किसी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग एक तिहाई समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। तात्पर्य यह कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं, सामान्यतः उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाने लगती हैं।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर सात में से एक किशोर डिप्रेशन का शिकार है। इंडियन जर्नल आफ साइकिएट्री में वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में पांच करोड़ से अधिक किशोर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं जूझ रहे थे। इनमें से ज्यादातर किशोर बेचैनी और डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना कर रहे थे। यूनिसेफ के अनुमान के मुताबिक कोरोना के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग बेचैनी से जूझ रहे हैं और 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। जर्नल 'द लैंसेट साइकिएट्री' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आस्ट्रेलिया में 75 प्रतिशत किशोर बेचैनी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था में लड़के-लड़कियों में कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं। उसी दौरान उन्हें बोर्ड परीक्षाओं एवं करियर के लिए कोर्स चयन जैसे दबावों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में, यदि उन्हें घर और स्कूल में उचित परिवेश नहीं मिले तो ये परिस्थितियां प्रायः उनमें बेचैनी और डिप्रेशन पैदा कर देती हैं।

इनके अतिरिक्त, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, साफ्ट ड्रिंक्स और इंटरनेट मीडिया भी बेचैनी और डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं। इन मामलों में क्लिनिकल केयर से अधिक जरूरत बच्चों को इन मानसिक बीमारियों से बचाने को लेकर रणनीति बनाए जाने की है। वहीं डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित माडल तैयार करने की बात कही गई है।

जिन्दगी की जरूरत क्यों नहीं रहीं किताबें?

विजय गर्ग

यह भी अजीब विरोधाभास है कि एक ओर जहां इंटरनेट से किताबों की उपलब्धता बढ़ गयी, वहीं दूसरी ओर किताबों के प्रति लोगों की रुचि कम हो गयी। सीमित सूचना के युग में असीमित ज्ञान के प्रति लोगों का रुझान कम क्यों हो गया?

दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो चुका है। पुस्तक मेला इस बार 1 फरवरी से 10 फरवरी आयोजित हो रहे हैं

किताबें इस संसार को बदलने का एक साधन रही है। पर हमारा समय ऐसा है कि अब किताबों का संसार ही बदल रहा है। यह बदलाव, विषय, प्रस्तुति, पाठक वर्ग, व्यापार सभी दिशाओं में गतिशील है।

देश के लेखकों और लेखकों के लिखे को प्रकाशित करने वाले जिस संसार को हम जानते रहे हैं, वह पूरी तरह बदल जाएगा, यह कभी सोचा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि किताबों की हमारी दुनिया सिर्फ अतीत की एक याद बनकर रह जाएगी? सोशल मीडिया और एक क्लिक पर जानकारी मिलने के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य किताबों से दूर चला आया है। जो किताबें संसार को बदलने का रहस्य लिए हमारे सिरहाने होती थीं, वे किसी सुदूर संसार की याद भर बनकर रह गई हैं।

1991 के बाद, उदारीकरण ने जहां देश में सामान्य उपभोग की वस्तुओं को सर्वसुलभ बनाने का काम किया, वहीं किताबों की दुकान कहीं खोने लगी। कागज और प्रिंटिंग की कीमतें इस तरह आसमान छूने लगीं कि छपी हुई किताबें प्रकाशन घर से लोगों के हाथों मे पहुंचते पहुंचते मध्यवर्गीय परिवार के बजट के बाहर छिटक गई। लेकिन इंटरनेट की क्रांति ने दूर देश की किताबें, लाखों किताबें पाठकों को एक क्लिक पर उपलब्ध करवा दी।

जो किताबें जाने कितनी जगह घेरती थी, और

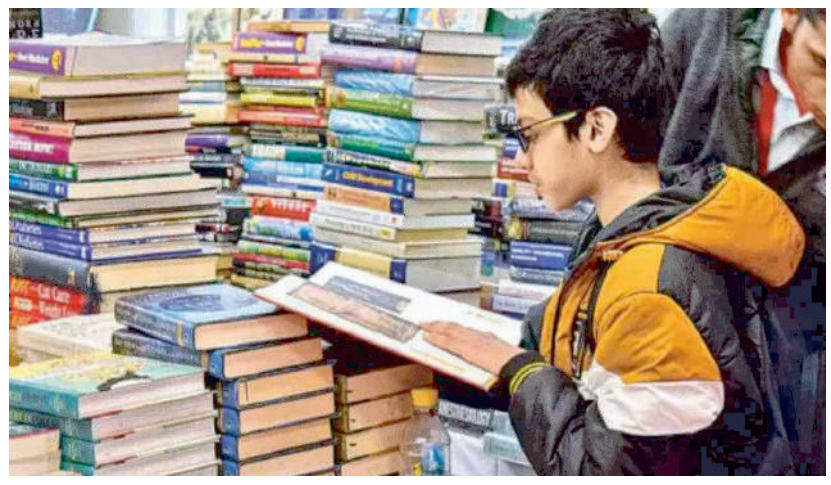

जाने कितनी दुर्लभ होती थी, अब आपके मोबाइल में हैं। ऐसा लगता है जैसे किताबों की दुनिया मोबाइल में समा गई। कम समय में सहज उपलब्ध कराने की तकनीकी के कारण किताबों का संसार भी डिजिटल रूप में घर घर पहुंच गया है। आम आदमी जिसके हिस्से कल तक 'सड़क का साहित्य' था, अगर आज उसकी पहुंच के दायरे में 'विश्व का श्रेष्ठ साहित्य' सिमट आया है तो उसका कारण इंटरनेट की क्रांति है।

एक अर्थ में देखा जाए तो यह किताबों की उपलब्धता की महाक्रांति है। किताबों के रूप बदले हैं, पर वे पहले से ज्यादा सुलभ हैं। हर जगह उपस्थित है। लेकिन जीवन शायद किताबों से दूर चला आया है। उनकी उपलब्धता जरूर बढ़ी है, पर महत्व और प्रभाव में कमी आई है। अब वे कल्पनाशक्ति को रचती नहीं है, न विचारों को गढ़ पाती है। उनकी ताकत कम हुई है। समाज में उनकी जगह कम हो रही है। अब वे किसी आदमी के एकांत में ऐसा उद्वेलन पैदा नहीं कर पा रहीं कि वह व्यक्ति कुछ और ही बन जाए। जिन किताबों ने लिंकन, गांधी, लेनिन, आइंस्टाइन जैसों को रचा था, और प्रकारांतर से युग को बदल देने का माध्यम बन गई थीं, आज बड़ी अशक्त सी हैं। मानों जिन्दगी को किताबों की जरूरत ही नहीं रही। जिंदगी अब कुछ और मांगती है।

यह कैसी विडंबना का समय है कि जब तकनीक और विज्ञान ने ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के रास्ते खोल दिए हैं, तो ठीक उसी समय उन रास्तों पर चलने वाले कदम कहीं खो गए हैं या फिर उनका चलना तो है, पर उस चलने से कोई यात्रा नहीं बनती, सिर्फ चलना रह जाता है। जीवन ऐसा बदला है कि उसमें गहराई के लिए बहुत जगह नहीं बची।

इंसान के पास उस एकांत का अभाव है, जिसमें वह खुद को निहार सके और रचना कर सके। उसके पास खुद तक पहुंच पाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह आज महज एक उपभोक्ता है। किताबों का भी वह महज उपभोक्ता है, यदि किताबों तक उसकी जिंदगी का कोई रास्ता जाता है, तो भी।

जीवन सिर्फ विकास की सरकारी परिभाषाएं नहीं है, उसका सौदर्य विराट है, उसके अर्थ असीम है, उसके आयाम विविध है। इस बदलते संसार में इंसान को खुद को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। उसे अपने लिए बदलते संसार को अपनी तरह से बदलना होगा, इस तरह कि उसकी खूबसूरती बची रहे, बढ़े और जिंदगी को सृजनात्मक रूप दे। किताबें विद्वता, आदर्श, धर्मशास्त्रगत की जड़वत दुनिया नहीं हैं, वे हमारी अंतरात्मा की हंसी और हमारे भीतर का पल्लवन है। संसार की बहुत-सी किताबें यशप्राप्ति, जड़ता, मिथ्या आचार के प्रचार से जन्मती हैं, और लोगों की जिंदगियों में आ कर उनके अस्तित्व को सीमित कर जाती हैं।

वे किताबें जो मानवीय व्यक्तित्व की जरूरत हैं, उनकी शिनाख्त की एक पगडंडी बनानी होगी और इस पर एक यात्रा रचनी पड़ेगी और यह जानना होगा कि विज्ञान और तकनीक इसमें बहुत सहायक है। बात जहां गलत हो जाती है, वह हमारे ही मन का कोई कोना है, जो भ्रम और हार को अपना सत्य मान लेता है। हमें जिंदगी को नए सिरे से खोजना होगा। किताबों को पढ़ने और औरों को भी पढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ना होगा। लेखक को भी शब्द वहीं मिलेंगे।

समय के बदलाव ने लेखक, पाठक के माध्यम बदल दिए है, लेकिन अभिव्यक्ति की अभिलाषा यानी एहसास और जज्बातों को लिखने की बैचेनी अब भी वही है, जो गालिब या मीर में थी। यह सत्य है कि तकिए के नीचे किताब रखकर सोने का जमाना अब बीतने वाला है। पाठकों और प्रकाशकों को इसके लिए तैयार रहना होगा। पुस्तक मेले में होने वाली बिक्री में धीरे धीरे आ रही गिरावट इस ओर इशारा कर रही है। एक प्रकाशक का कहना है कि पुस्तक मेले में भीड़ बहुत आती है, पाठक कम आते है। उम्मीद है पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों को किताबें खरीदकर पढ़ने के लिए प्रेरित करने में सफल रहेगा।

समग्र शिक्षा भविष्य के रोजगार में सुधार कर सकती है

विजय गर्ग

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, स्कूली शिक्षा की सफलता न केवल छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों पर, बल्कि उनके सामाजिक और भावनात्मक सीखने को बढ़ाने पर भी टिका है।

सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 1.47 मिलियन स्कूलों में 248 मिलियन छात्रों को पूरा करती है, जो 9.8 मिलियन शिक्षकों द्वारा समर्थित है।

सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 1.47 मिलियन स्कूलों में 248 मिलियन छात्रों को पूरा करती है, जो 9.8 मिलियन शिक्षकों द्वारा समर्थित है।

आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य में कार्यबल की रोजगार में सुधार करने के लिए समग्र शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। यह एक दूसरे के पूरक के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा मॉडल की आवश्यकता पर भी जोर देता है, एक आवश्यक आवश्यकता जो महामारी के बाद उभरी।

सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 1.47 मिलियन स्कूलों में 248 मिलियन छात्रों को पूरा करती है, जो 9.8 मिलियन शिक्षकों द्वारा समर्थित है। सरकारी स्कूल इन संस्थानों में से 69% का गठन करते हैं, जिसमें 51% शिक्षण स्टाफ के साथ छात्र आबादी का 50% शिक्षित होता है। इसके विपरीत, निजी स्कूल 22.5% स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 38% शिक्षकों के साथ 32.6% छात्रों को पढ़ाते हैं।

2020 तक 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने वाला लक्ष्य। वर्तमान में, GER प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक है, 93% पर। द्वितीयक स्तर (77.4%) और उच्च माध्यमिक स्तर (56.2%) पर नामांकन अंतराल को बंद करने के लिए पहल की जा रही है, देश को सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा के अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। GER उस आयु वर्ग की आबादी की तुलना में एक स्तर की शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत है।

ड्रॉपआउट दर में गिरावट

इसके अलावा, हाल के वर्षों में स्कूल ड्रॉपआउट दरों में लगातार गिरावट देखी गई है, अब प्राथमिक के लिए 1.9%, उच्च प्राथमिक के लिए 5.2% और माध्यमिक शिक्षा के लिए 14.1% है। इन सुधारों के बावजूद, चुनौतियां छात्र प्रतिधारण में बनी रहती हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए 85.4% (कक्षाएं I से v), प्राथमिक के लिए 78% (कक्षा I से VIII से), माध्यमिक के लिए 63.8% (कक्षाएं I से x), और 45.6% उच्च माध्यमिक के लिए (कक्षाएं I से XII से)

कंसल्टिंग फर्म डेलॉइट इंडिया के पार्टनर कमलेश व्यास ने कहा, 'स्कूली बच्चों के बीच ड्रॉपआउट दरें स्कूलों में कम हो गई हैं, लेकिन वे प्राथमिक स्कूलों के लिए 1.9%, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 5.2% और माध्यमिक विद्यालयों में 14.1% हैं।'

'इन सभी छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में या स्कूलों में वापस रखने की आवश्यकता है, अगर हमें अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। डेटा हमें क्या नहीं बताता है कि बच्चों की साक्षरता और संख्यात्मकता का स्तर है जो बाहर नहीं जा रहे हैं। एक फोकस क्षेत्र भी बनें, 'उन्होंने कहा।

स्कूली शिक्षा की सफलता न केवल छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों पर बल्कि उनके सामाजिक और भावनात्मक सीखने (एसईएल) को बढ़ाने पर भी टिका है। 'एक अच्छी शिक्षा एक बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और जीवन कौशल को बढ़ाती है,' सर्वेक्षण में कहा गया है। यह कार्यबल में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करता है।

यद्यपि ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल तकनीक ने शैक्षिक पहुंच को व्यापक बनाया है, लेकिन कक्षा-आधारित शिक्षा का समय-सम्मानित दृष्टिकोण अभी भी महत्वपूर्ण मूल्य को बनाए रखता है। तमिलनाडु सरकार ने एक लागत प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम पेश किया है, जो शिक्षा को सीधे छात्रों के दरवाजे पर लाता है। इस पहल का उद्देश्य महामारी की शैक्षिक असमानताओं को पाटना, इक्विटी को बढ़ावा देना और सीखने के परिणामों को बढ़ाना है।

गली का खेल, यादें का मेल,....

विजय गर्ग

बचपन, वह समय जब ज़िंदगी किसी स्कूल की घंटी या होमवर्क की कॉपी में नहीं बंधी होती थी। वह समय जब खुशियां गली-मोहल्ले के छोटे-से मैदान में सिमटी होती थीं और उन ख़ुशियों का सबसे ख़ूबसूरत हिस्सा था 'इलास्टिक बैंड'। सोचती हूं, कितना साधारण-सा तो खेल था। बस एक लंबा इलास्टिक, जो किसी पुरानी सिलाई किट या मम्मी की नज़र से बचाकर चुपके से उठा लिया जाता था। लेकिन उस साधारण इलास्टिक में बचपन की सबसे रंगीन यादें बंधी हुई हैं। आजकल के बच्चों को सुनकर लगेगा कि इलास्टिक बैंड, ये भी कोई खेल हो सकता है भला। जी हां, हो सकता है और वो भी बहुत ही मज़ेदार ।

'चलो, इलास्टिक बैंड खेलते हैं!' जैसे ही ये आवाज़ गली में गूंजती, चारों ओर से लड़कियां अपनी चोटी संवारती और सरपट दौड़ी चली आतीं। कोई घर से अपनी चप्पल उतारकर आती तो कोई अपनी मां की डांट सुनने के बावजूद, बस खेलने को तैयार रहती । खेल का मैदान हुआ करती थी एक गली जिसकी दीवारों पर सफेदी झर रही होती थी और फ़र्श पर बारिश की बूंदों के पुराने निशान । यही गली हमारी दुनिया थी। यहां हर कूद, हर जीत, हर हार, और हर गिरावट में हमारे सपने बसते थे।

दुनिया से बेख़बर होकर जब खेल की शुरुआत होती तो इलास्टिक दो लड़कियों के पैरों पर कसकर बांध दिया जाता। पहले दौर में इलास्टिक नीचे रहता, सिर्फ़ टखनों तक । खेल के नियम के अनुसार खिलाड़ी को पहले इलास्टिक की दोनों लाईनों के बीच में कूदना होता था और दूसरी तरफ़ जाना होता था। अगले स्टेप में कूदते हुए दोनों पैरों से इलास्टिक को दबाते जाना होता था, और फिर एक तरफ़ की इलास्टिक को पैरों में फांसकर दूसरे इलास्टिक के पार करना होता था जो एक त्रिकोण जैसा आकार ले लेता था। फिर उसे छोड़कर एक और छलांग लगानी होती थी और वापस आते हुए दोबारा दोनों इलास्टिक को दोनों पैरों से दबाते हुए आना होता था । आख़िरी स्टेप होता जब दोनों इलास्टिक के बीच में कूदकर एक खिलाड़ी की ओर मुख कर के दोनों पैरों से दोनों अलग इलास्टिक को एक साथ, फिर दोनो पैर बाहर की तरफ़ और फिर वापस अंदर आना होता था, अंत में खिलाड़ी को वापस अपनी जगह पर छलांग लगाकर लौट जाना होता था। इस समय तक तो खेल आसान सा लगता था लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता, इलास्टिक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगता घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर कंधों तक। हर एक स्टेज पार करने के बाद खेल मुश्किल होता चला जाता था, इतना ऊंचा कूद पाना सबके बस की बात नहीं थी। जब मैं पहली बार कूदने को तैयार होती तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी बड़ी लड़ाई के लिए उतर रही हूं। मन में डर और जोश का अजीब सा मिश्रण होता । 'एक, दो, तीन!' ये कहते हुए छलांग मारती और अगर पार कर जाती तो ऐसा लगता जैसे मैंने दुनिया ही जीत ली हो। लेकिन ये खेल तो हार-जीत का था ही नहीं। खेल की मुश्किल बढ़ते हुए कई बार मेरे पैर उलझ जाते और मैं इलास्टिक के बंधन में गिर पड़ती। उस गिरने पर दोस्तों की हंसी गूंजती । वह हंसी उपहास नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो तो फिर से उठने का हौसला देती थी।

जब भी कोई साथी इलास्टिक बैंड पार करता या करती तो गली में ख़ुशी की गूंज सुनाई देती। लड़कियों की तालियां और चीख़ तो पूरे मोहल्ले को जगा देती थी। कोई 'वाह, कमाल कर दिया!' कहता, तो कोई अगली बार और ऊंचा कूदने का चैलेंज देता। हमारे बीच कोई प्रतियोगिता

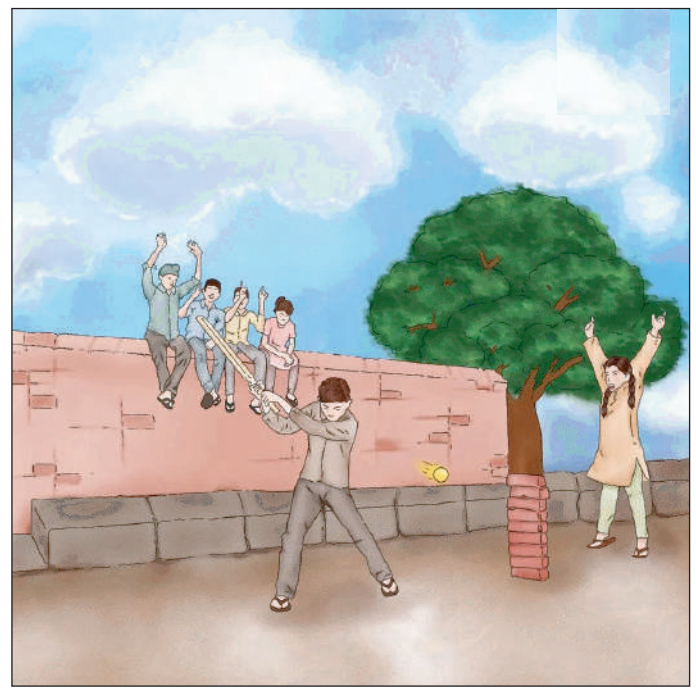

नहीं थी, लेकिन एक अदृश्य बंधन था। वो ऐसा दौर था जब सब लोग मिलकर एक-दूसरे को प्रेरित करते, हंसते, और कभी-कभी छुप-छुपकर चीटिंग भी करते। यह खेल सिर्फ़ शरीर को ही नहीं, हमारे दिलों को भी जोड़ता था।

आज जब मैं एक बड़े शहर के ऑफिस में बैठकर यह सब सोचती हूं तो दिल फिर से उसी गली में लौट जाना चाहता है। लगता है जैसे वो इलास्टिक बैंड मेरी यादों का पुल हो जो मुझे बचपन से जोड़ता है। अब बच्चे शायद इलास्टिक बैंड के खेल को न समझ पाएं। उनके पास वीडियो गेम है, मोबाइल है, टैब है, लेकिन इस सब में वो मासूमियत कहां, जो हम गली के उस छोटे से खेल में महसूस करते थे?

कभी-कभी, जब मैं पुराने सामान को टटोलती हूं और अगर कभी कहीं से कोई इलास्टिक हाथ में आ जाता है तो उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान ख़ुद-ब-ख़ुद आ जाती है। ऐसा लगता है, जैसे वो इलास्टिक आज भी मेरे अंदर बसी उस बच्ची को जगा रहा है जो गिरने के डर से बेफ़िक्र होकर कूदना चाहती थी। इलास्टिक बैंड एक साधारण खेल हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपी जो यादें और भावनाएं जी गई हैं वो किसी ख़जाने से कम नहीं। ख़ुशी तो हर छलांग में छुपी होती है चाहे वो छलांग कितनी भी छोटी क्यों न हो। तो अगली बार जब आप किसी पुराने इलास्टिक को देखें, तो पलभर के लिए अपने बचपन को फिर से जी लीजिए। कौन जाने, वह इलास्टिक आपको अपने भीतर सिमटी गली की उस सबसे प्यारी यादों से फिर से जोड़ दे।

ट्रंप ने दिया सरप्राइज, सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी; अब आगे क्या?

परिवहन विशेष न्यूज

एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप ने टैरिफ पर जो अस्थायी रोक लगाई है उससे बाजार को सोमवार की गिरावट से उबरने में मदद करेगी। अब निवेशकों का ध्यान यूनियन बजट पर केंद्रित हो गया है जो पहले व्यापार संबंधी चिंताओं के कारण प्रभावित था। साथ ही निवेशकों को उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का एलान भी कर सकता है। इससे बाजार में तेजी आएगी।

नई दिल्ली। भारत का शेयर बाजार सोमवार को क्रैश कर गया था। लेकिन, आज इसने जोरदार तरीके से बाउंसबैक किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स 148.85 अंकों (0.64%) की बढ़त के साथ 23,509.90 पर खुला। वहीं, बीएसई सेंसेक्स 500.86 अंकों (0.65%) की मजबूती के साथ 77,687.60 पर पहुंच गया। सुबह करीब 10 बजे तक दोनों प्रमुख सूचकांक में करीब एक-एक फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा था। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में तेजी की क्या वजह है और क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बाजार में आई तेजी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शेयर बाजार को लगातार सरप्राइज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लगाने का एलान किया था। इससे दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका छिड़ गई थी और जापान, दक्षिण कोरिया के साथ भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश कर गया था। हालांकि, अब ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की योजना को स्थगित कर दिया है। इससे भारत समेत दुनियाभर के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है।

शेयर मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है?

एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप ने टैरिफ पर जो अस्थायी रोक लगाई है, उससे बाजार को सोमवार की गिरावट से उबरने में मदद करेगी। अब निवेशकों का ध्यान यूनियन बजट पर केंद्रित हो गया है, जो पहले व्यापार संबंधी चिंताओं के कारण प्रभावित था। साथ ही, निवेशकों को उम्मीद है कि आरबीआई की एमपीसी में ब्याज दरों में कटौती का एलान भी हो सकता है, जिसके नतीजे 7 फरवरी को आएंगे।

बैंकिंग और मार्केट विशेषज्ञ अजय बग्गा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, 'यूनियन बजट से मिले सकारात्मक संकेत बाजार को समर्थन देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शुक्रवार, 7 फरवरी को ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है। बाजार आज अमेरिकी और एशियाई बाजारों के नक्शेकदम पर चलकर कुछ हद तक रिकवरी कर सकता है।'

उन्होंने आगे कहा, ₹ट्रम्प की नीतियों के अनुसार ट्रेडिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मुद्रा बाजार से लेकर शेयर बाजार, कमोडिटीज़ और यहां तक कि क्रिप्टो एसेट्स तक, सभी में सोमवार रात और मंगलवार सुबह उथल-पुथल देखने को मिली। मेक्सिको और कनाडा को ट्रम्प टैरिफ से 30 दिनों की राहत मिली है, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और एक नए समझौते पर बातचीत करने पर सहमति जताई है।₹

क्या शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी?

एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल वैश्विक स्तर पर काफी अनिश्चितता है। खासकर, ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर। उन्होंने चीन पर टैरिफ जारी रखी है। अगर ट्रंप दूसरे देशों पर भी टैरिफ लगाते हैं, तो इससे टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका है। इसका मतलब है कि निकट अवधि में शेयर बाजार अस्थिर बना रहेगा।

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कटौती करके काफी राहत दी है। इससे खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुछ ऐसा ही कदम आरबीआई भी ब्याज दरों में कटौती करके उठा सकता है। इससे बाजार को बूस्ट मिलेगा।

सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त

NSE के अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में थे, सिवाय निफ्टी FMCG के, जो नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहा था। निफ्टी ऑटो में 1.58% की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी PSU बैंक 1.72% से अधिक उछला, जिससे बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों का भरोसा मजबूत होता दिखा।

निफ्टी 50 इंडेक्स के 50 शेयरों में से 40 हरे निशान में थे, जबकि 11 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजार धारणा पॉजिटिव बनी रही, जिसका सपोर्ट ग्लोबल मार्केट ने किया।

एशियाई बाजारों में भी तेजी

शेयर बाजार में तेजी सिर्फ घरेलू स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि एशियाई बाजारों में भी मजबूत बढ़त देखी गई।

जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1% से अधिक चढ़ा।

हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2.48% उछला।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.5% मजबूत हुआ।

नए शिखर पर पहुंचा सोना, आखिर किस वजह से बढ़ रहे भाव?

सोने की कीमत में उछाल पिछले पांच दिनों से गोल्ड की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। यह नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। हालांकि चांदी के भाव में पांच दिन की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है।

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिली। इसने अब नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। यह 500 रुपये बढ़कर 85,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, ज्वैलर्स और रिटेलर्स की मजबूत मांग के कारण सोने के दामों में यह उछाल देखने को मिला।

सोने-चांदी के भाव का हिसाब-किताब

पिछले सत्र में सोना (Gold Price) ₹85,300 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस साल 1 जनवरी से अब तक सोने की कीमत ₹6,410 (8.07%) बढ़ चुकी है।

चांदी में 5 दिन की तेजी पर ब्रेक, भाव ₹500 गिरकर ₹95,500 प्रति किलो हुआ।

क्या है कमोडिटी एक्सपर्ट की राय

Abans Holdings के CEO चिंतन मेहता का कहना है कि सोने के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की वजह ग्लोबल ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) की आशंका है। अब निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। ट्रंप ने पहले मेक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाई और फिर उस पर अस्थायी रोक भी लगा दी। इससे गोल्ड को लेकर अनिश्चितता और भी ज्यादा बढ़ी है।

वहीं, LKP Securities में वाइस प्रेसिडेंट Jateen Trivedi का कहना है कि सोने की तेजी थोड़ी धीमी हुई क्योंकि MCX पर यह ₹83,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। त्रिवेदी के मुताबिक, यह कमजोरी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच टैरिफ चर्चा के कारण आई है।

सोने के बढ़ते भाव की वजह क्या है?

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने व्यापार जगत में अनिश्चितता को काफी बढ़ा दिया है।

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आर्थिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सोना खरीद रहे हैं।

चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार दूसरे महीने अपने सोने के भंडार में इजाफा किया है।

भारत में शादी के सीजन के चलते सोने के गहनों की डिमांड भी काफी ज्यादा है।

अमेरिकी डेटा पर निवेशकों की नजर

अमेरिका का JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) डेटा और फैक्ट्री ऑर्डर डेटा जारी होगा। निवेशकों की इस पर बारीक नजर रहेगी। इस डेटा के बाद अमेरिकी डॉलर और सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। HDFC Securities में कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी का कहना है, 'इस डेटा से अमेरिकी डॉलर को रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे सोने की कीमतों पर असर पड़ेगा।'

क्लर्क से लेकर सिविल सेवा अधिकारी तक, किसकी सैलरी में कितना होगा इजाफा?

tपरिवहन विशेष न्यूज

आठवां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की अवधि अगले साल खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। फिर केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। आइए जानते हैं कि लेवल वाइज किस केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest updates) के साथ लेवल वाइज केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा बदलाव होगा।

8वें वेतन आयोग में लेवल वाइज कितनी सैलरी बढ़ेगी?

8वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से होगी। एक्सपर्ट का अनुमान है कि यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। आइए समझते हैं कि अगर अधिकतम 2.86 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो लेवल वाइज केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।

लेवल 1 की बात करें, तो इसमें चपरासी, अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। इनका मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है। यह 2.86 फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसका मतलब कि सैलरी में 33,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

लेवल 2 में लोअर डिविजन के क्लर्क आते हैं। इनका मूल वेतन फिलहाल 19,900 रुपये है। यह 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 56,914 रुपये तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों को 37,014 रुपये की हाइक मिल सकती है।

लेवल 3 में कॉन्स्टेबल या स्किल स्टाफ शामिल होते हैं। उन्हें अभी 21,700 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से इनका वेतन 40,362 रुपये बढ़कर 62,062 रुपये तक पहुंच जाएगा।

लेवल 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी फिलहाल 25,500 रुपये है। यह 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 72,930 रुपये हो सकता है। इसका मतलब हाइक 47,430 रुपये की होगी।

लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च-स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। उनकी बेसिक सैलरी अभी 29,200 रुपये है। इसके 83,512 रुपये हो जाने का अनुमान है। यह 54,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

लेवल 6 में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर आते हैं। उनका मूल वेतन 35,400 रुपये है, जो संशोधित होने के बाद 1,01,244 रुपये हो सकता है। यह 65,844 की वृद्धि होगी।

लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स और सहायक इंजीनियर शामिल हैं। उनकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है, जो 1,28,414 रुपये की जा सकती है। यह 83,514 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

लेवल 8 के सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स आते हैं। उनकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपये महीना है। यह 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 1,36,136 हो सकती है। इसका मतलब है कि इसमें 88,536 रुपये की वृद्धि होगी।

लेवल 9 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और अकाउंट ऑफिसर्स आते हैं। उनका का मूल वेतन अभी 53,100 रुपये है। इसमें 98,766 रुपये का इजाफा हो सकता है। फिर इन्हें हर महीने 1,51,866 रुपये मिलेंगे।

लेवल 10 में सिविल सर्विसेज में एंट्री लेवल के अधिकारी, जैसे कि ग्रुप ए अफसर शामिल हैं। उन्हें अभी हर महीने 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से उनका उनका मूल वेतन 1,60,446 हो सकता है, जो 1,04,346 की बढ़ोतरी होगी।

नए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में क्या होगा खास, किन सुधारों पर रहेगा सरकार का फोकस?

परिवहन विशेष न्यूज

मौजूदा प्रत्यक्ष कर संहिता पढ़ने और समझने दोनों में काफी जटिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक मान लीजिए किसी एक प्रावधान के बारे में पेज नंबर 10 पर लिखा है तो उसी प्रावधान से जुड़े दूसरे क्लाज पेज नंबर 110 पर दिए गए हैं। आदर्श स्थिति में उसे समान पेज पर होना चाहिए। मौजूदा संहिता में ऐसी कई सारी विसंगतियां है जिन्हें नए डायरेक्ट टैक्स कोड में दूर किया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर की नई संहिता (New Direct Tax Code 2025) तकनीक व पारदर्शिता पर आधारित होगी। यह डेटा पर आधारित नीति होगी, जो टैक्सपेयर्स के मित्र के रूप में काम करेगी। इसकी भाषा को बिल्कुल सरल किया जा रहा है।

बजट की बारीकियों को समझने के लिए औद्योगिक संगठन सीआईआई की तरफ से मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में अग्रवाल ने कहा कि विभाग इनकम टैक्स संबंधी प्रविधान व नियमों को लगातार सरल बनाने में लगा हुआ है। बजट में प्रत्यक्ष कर की नई संहिता लाने की घोषणा की गई है जिसे अगले महीने संसद में पेश किया जाएगा।

मौजूदा टैक्स कोड में क्या दिक्कत है?

हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि नई संहिता से जुड़ा बिल संसद में पेश होने के बाद संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। उनकी सिफारिशों के बाद ही संहिता पर अंतिम फैसला होगा। वर्तमान में प्रत्यक्ष कर संहिता पढ़ने और समझने दोनों में काफी जटिल है।

विशेषज्ञों के मुताबिक मान लीजिए किसी एक प्रावधान के बारे में पेज नंबर 10 पर लिखा है तो उसी प्रावधान से जुड़े दूसरे क्लाज पेज नंबर 110 पर दिया गया है ,जबकि उसे समान पेज पर होना चाहिए। वर्तमान संहिता में इस प्रकार की कई सारी विसंगतियां है।

आय को इनकम टैक्स से छिपाना आसान नहीं

सीडीबीटी चेयरमैन ने कहा कि लोगों की आय की ट्रैकिंग के लिए अब विभाग तकनीकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए विभाग की नजर से आय को छिपाना अब आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का मुख्य उद्देश्य आय को ट्रैक करना होता है। लेकिन ट्रैकिंग के लिए अब टीडीएस की जरूरत नहीं है।

तभी बजट में टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है। टीडीएस-टीसीएस संबंधी गलती से जुड़े नियमों के अपराधीकरण को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स संबंधी अपील के त्वरित निपटान पर भी काम किया जा रहा है।

सीमा शुल्क का रिफंड अब एक माह में

सीआईआई के कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजट में विदेश व्यापार के प्रोत्साहन के लिए सीमा शुल्क रिफंड को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अभी अगर कोई व्यापारी गलती से सीमा शुल्क अधिक दे देता है तो जटिल प्रक्रिया की वजह से उस शुल्क को वापस लेने में सालभर का समय लग जाता था।

अब वह व्यापारी स्वैच्छिक दावा कर एक माह के अंदर उस शुल्क को वापस ले सकेगा। कच्चे माल का आयात करके उससे भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने पर शुल्क में छूट का प्रविधान है। लेकिन इस छूट को हासिल करने में कारोबारियों को कई जटिल प्रक्रिया को पूरा करना होता है। बजट में इन नियमों में भी संशोधन किया गया है।

शेयर बाजार से जुड़ा है देश का हर पांचवां घर, FPI के बराबर पहुंची रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी

पिछले पांच महीनों के दौरान एक करोड़ निवेशक शेयर बाजार से जुड़े हैं। 2024 में 2.32 करोड़ नए निवेशक बाजार में आए जो किसी एक साल में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। एनएसई की एक रिपोर्ट में शेयर बाजार में निवेश के जरिये भारतीय परिवारों की कमाई भी बताई गई है। पिछले पांच साल में शेयर बाजार में पारिवारिक संपत्ति 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी है।

मुंबई। नेशनल स्टाक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में पिछले दशक में छह गुना की वृद्धि हुई है। देश का प्रत्येक पांचवां घर शेयर बाजारों से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शेयर बाजार निवेश से जुड़े खातों की संख्या 21 करोड़ को पार कर गई है। इसमें 18 करोड़ से अधिक डीमैट खाते हैं।

पिछले पांच महीनों के दौरान एक करोड़ निवेशक शेयर बाजार से जुड़े हैं। अकेले वर्ष, 2024 में 2.32 करोड़ नए निवेशक बाजार में आए, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। रिपोर्ट में शेयर बाजार में निवेश के जरिये भारतीय परिवारों की संपत्ति सृजन पर भी प्रकाश डाला गया है।

पिछले पांच साल के दौरान शेयर बाजार में पारिवारिक संपत्ति बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी है। बीते तीन सालों के दौरान इनकी संपत्ति में 28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वृद्धि हुई है। अकेले वर्ष 2024 में, घरेलू निवेशकों की संपत्ति में 13.2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

संपत्ति का अनुमान एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में प्रत्यक्ष स्टॉक निवेश और म्यूचुअल फंड दोनों के माध्यम से व्यक्तिगत होल्डिंग में वार्षिक परिवर्तन पर आधारित है। रिपोर्ट में यह माना गया है कि व्यक्तियों के पास म्यूचुअल फंड निवेश का उतना ही हिस्सा है जितना कि वे इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में रखते हैं।

व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी एफपीआई के बराबर

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय निवेशकों का शेयर बाजार में विश्वास बरकरार है। एनएसई ने कहा कि सितंबर, 2024 तक व्यक्तिगत निवेशकों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय शेयर बाजार में हिस्सेदारी 17.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की हिस्सेदारी के लगभग बराबर है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत होल्डिंग की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक था।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफपीआई जहां फंड निकाल रहे हैं, वहीं मजबूत घरेलू प्रवाह ने बाजार को स्थिर रखा है। भारतीय परिवारों की इक्विटी में भागीदारी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक निवेशक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और धन सृजन जारी है। अगले कुछ साल में भारतीय परिवारों की भागीदारी नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है।

नारायण मूर्ति से भी आगे निकले मस्क, कर दी 120 घंटे काम करने की वकालत; सोशल मीडिया यूजर्स भड़के

एलोन मस्क की कार्य नीति मस्क ने लंबे काम के घंटों की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि DOGE के कर्मचारी हफ्ते में 120 घंटे तक काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा जो हफ्ते में 40 घंटे काम करने का दावा करते हैं। मस्क का कहना है कि विरोधी शायद इसी वजह से पीछे छूट रहे हैं।

नई दिल्ली। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने वर्क लाइफ बैलेंस पर नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि एक हफ्ते में 120 घंटे काम करना चाहिए। वह इतना काम करने वालों की तारीफ कर रहे हैं और इसे 'सुपरपावर' जैसा बता रहे हैं। अभी भारत में 70 से 90 घंटे के वर्किंग आवर्स पर बहस हो रही थी। लेकिन, मस्क इससे भी दो कदम आगे निकल गए।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत में मस्क का काफी अहम योगदान रहा है। ट्रंप सरकार ने मस्क को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। वह 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (DOGE) के प्रमुख है, जिसका काम सरकार को खर्च का बोझ कम करने के रास्ते सुझाना है। साथ ही, भ्रष्टाचार और प्रशासन से जुड़ी अन्य समस्याओं को जड़ से खत्म करना है।

वीकेंड पर काम करने को बताया सुपरपावर

मस्क ने लंबे काम के घंटों की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि DOGE के कर्मचारी हफ्ते में 120 घंटे तक काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा, जो हफ्ते में 40 घंटे काम करने का दावा करते हैं। मस्क का कहना है कि विरोधी शायद इसी वजह से पीछे छूट रहे हैं।

टेक अरबपति ने वीकेंड में काम करने को 'सुपरपावर' बताया। साथ ही कहा कि नौकरशाही के विरोधी 'बहुत मोटा हो रहे हैं' क्योंकि वे हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'नौकरशाही में बहुत कम लोग असल में वीकेंड पर काम करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि विरोधी टीम 2 दिनों के लिए पूरी तरह से मैदान छोड़ देती है!'

मस्क पर भड़के इंटरनेट यूजर्स

एलन मस्क के 120 घंटे काम करने के बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी कड़ी आलोचना करने लगे। कुछ तो उन्हें 'टेरिबल बॉस' तक बता दिया। एक यूजर कुछ आंकड़े दिए, जिनसे पता चलता है कि Doge कर्मचारी हफ्ते में दो दिन छुट्टी लेते हैं, बाकी सभी दिन वे 24 घंटे काम करते हैं। उसने लिखा, ₹तो... Doge एलियंस और रोबोट से बना है! या फिर मस्क खुद को बेहतर दिखाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं।₹

हालांकि, कुछ यूजर ने मस्क और DOGE के वर्क कल्चर की तारीफ भी की। एक ने लिखा, "यह डिपार्टमेंट और मस्क ₹दलदल के खिलाफ जंग में नायक हैं₹। यूजर ने मस्क की तुलना नेपोलियन से की और कहा कि उनके पास बुद्धि, ऊर्जा और नैतिकता का अथाह भंडार है।

भारत में भी 70-90 घंटे की बहस

भारत में वर्क लाइफ बैलेंस काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा था कि नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। एलएंडटी के सीईओ एसएन सुब्रहमण्यम ने भी हफ्ते में 90 घंटे काम की बात कही।

वहीं, आम बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने का सेहत पर हानिकारक असर होता है। खासकर, यह इंसान के मानसिक सेहत पर काफी बुरा प्रभाव डालती है।

भाषा और पठन-पाठन की बेहतर समझ की ओर बढ़ता 'निपुण भारत'

हालिया वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि ग्रेड III के विद्यार्थियों ने अपने पढ़ने के कौशल (24% से 34%) और घटाव के कौशल (29% से 41%) में सुधार किया है। श्रगतिका घोष जैसे युवा पाठक इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे जीवंत और प्रासंगिक कार्यपुस्तिकाओं को अपनाने से ओडिशा में साक्षरता परिणामों में सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रवि शर्मा द्वारा गीतों के माध्यम से गणित पढ़ाया जाता है। जैसे-जैसे वे संख्याएँ सीखते हैं, वे नारा लगाते हैं, ₹एक-दो थैला लो, तीन-चार चलो बाज़ार।₹ दूसरी कक्षा की छात्रा श्रगतिका घोष अब आत्मविश्वास के साथ ओडिया पुस्तकें पढ़ सकती है। रंगीन और प्रासंगिक कार्यपुस्तिकाएँ कोर साक्षरता को बढ़ाती हैं।

प्रियंका सौरभ

शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की, जो समझ और अंकगणित के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का हर बच्चा 2026-2027 तक ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और अंकगणित समझ हासिल कर ले। निपुण भारत मिशन को केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में लॉन्च किया गया है; यह स्कूली शिक्षा के बुनियादी वर्षों में छात्रों तक पहुँच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने, शिक्षक क्षमता का निर्माण करने, सीखने के परिणामों की दिशा में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखने और उच्च गुणवत्ता वाले और विविध छात्र और शिक्षक संसाधन / शिक्षण सामग्री विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालिया वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट बुनियादी सीखने के परिणामों में महत्त्वपूर्ण सुधार का खुलासा करके आशा की किरण प्रदान करती है, विशेष रूप से ग्रेड III में। यह विकास आंशिक रूप से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार के ठोस प्रयासों के कारण है, जिसमें निपुण भारत मिशन एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा स्थापित की। इसने प्रारंभिक शिक्षा को समग्र शैक्षिक विकास के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में बल दिया। निपुण भारत मिशन एक गेम चेंजर 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय पठन, समझ और संख्यात्मकता पहल (निपुण) भारत, शिक्षा मंत्रालय का एक मिशन है। निपुण भारत का लक्ष्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के पढ़ने, लिखने और अंकगणित कौशल में सुधार करना है। निपुण भारत के घटक हैं अपनी मौखिक भाषा सुनने की समझ, शब्दावली और बातचीत करने की क्षमताओं में सुधार करें। प्रतीकों और ध्वनियों के बीच सम्बंध सीखकर लिखित शब्दों को पढ़ना सीखें, रोजमर्रा की स्थितियों को हल करने के लिए सरल गणित विचारों का उपयोग करने के लिए मौलिक संख्यात्मकता सीखें। निपुण भारत कार्यान्वयन के लिए योजनाएँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा बनाई जाती हैं।

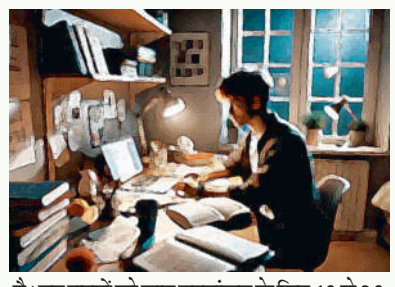

सीखने के स्तर को समझने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बुनियादी सीखने के शोध को अंजाम देती है। निपुण भारत की विशेषताओं में दिलचस्प पाठ्यक्रम और शिक्षण-शिक्षण संसाधन शामिल हैं जिनकी लागत प्रति बच्चा 500 रुपये है। यह प्रत्येक शिक्षक को संसाधन सामग्री के लिए 150 रुपये और उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों के लिए 5, 000 रुपये देता

है। यह राज्यों को छात्र मूल्यांकन के लिए 10 से 20 लाख रुपये और राज्य और जिला-स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच देता है। निपुण भारत अभियान के प्रभाव की कहानियों के अनुसार, शिक्षक गणित को अधिक रोचक बनाने के लिए गीतों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हालिया वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि ग्रेड III के विद्यार्थियों ने अपने पढ़ने के कौशल (24% से 34%) और घटाव के कौशल (29% से 41%) में सुधार किया है।

श्रगतिका घोष जैसे युवा पाठक इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे जीवंत और प्रासंगिक कार्यपुस्तिकाओं को अपनाने से ओडिशा में साक्षरता परिणामों में सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रवि शर्मा द्वारा गीतों के माध्यम से गणित पढ़ाया जाता है। जैसे-जैसे वे संख्याएँ सीखते हैं, वे नारा लगाते हैं, ₹एक-दो थैला लो, तीन-चार चलो बाज़ार।₹ दूसरी कक्षा की छात्रा श्रगतिका घोष अब आत्मविश्वास के साथ ओडिया पुस्तकें पढ़ सकती है। रंगीन और प्रासंगिक कार्यपुस्तिकाएँ कोर साक्षरता को बढ़ाती हैं। निपुण आवश्यक है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं। प्रारंभिक शैक्षणिक प्रगति के बाद, कई बच्चे बाद की कक्षाओं में संघर्ष करते हैं। हाशिए पर पड़े बच्चे अक्सर बुनियादी क्षमताओं की कमी के साथ स्कूल में प्रवेश करते हैं। निपुण भारत को परिणाम देने में चार साल लगे। यदि इसे 2030 तक बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव अधिक होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) में निवेश करना और कक्षा III-V को सीखने का समर्थन प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

जैसे-जैसे वे अधिक जटिल विचारों की ओर बढ़ते हैं, कई बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा के साथ संघर्ष करते हैं। प्रारंभिक तैयारी की कमी हाशिए के समुदायों के लिए अतिरिक्त बाधाएँ पैदा करती है। निपुण भारत की चार साल की यात्रा से पता चलता है, प्रणालीगत परिवर्तन के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता होती है। अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव डालने के लिए, निपुण 2.0 को 2030 तक बढ़ाया जा रहा है। उच्च-क्रम और बुनियादी कौशल के बीच ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए ग्रेड III-V तक विस्तार, प्रीस्कूल निर्देश को बेहतर बनाने और प्राथमिक विद्यालय के लिए छात्रों की तैयारी बढ़ाने के लिए प्रारंभिक बचपन शिक्षा को प्राथमिकता दें। नतीजे दर्शाते हैं कि सही संसाधनों और नीतियों के साथ विकास संभव है। निपुण भारत के विस्तार का लक्ष्य जीवन को बदलना है, न कि केवल संख्या बढ़ाना। भारत के पास सभी बच्चों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी देने और निपुण 2.0 के लिए तुरंत प्रतिबद्ध होकर बुनियादी शिक्षा में विश्वव्यापी मानक स्थापित करने का मौका है।

निपुण भारत कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रत्येक बच्चे की भाषा, लेखन, सीखने और पढ़ने की बेहतर समझ उल्लेखनीय है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को समझ और संख्यात्मकता में राष्ट्रीय पहल प्रवीणता सिखाना है।

-प्रियंका सौरभ

राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस

हमेशा 5 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस (जिसे राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस के रूप में भी जाना जाता है) मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण मौसम विज्ञान में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मानित करता है। यह दिन स्वैच्छिक तूफान स्पॉटर्स, पर्यवेक्षकों और मौसम के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को भी सम्मानित करता है।

मौसम कर्मी दिवस यह वार्षिक अवकाश जॉन जेफ्रीज़ के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1744 में इसी दिन हुआ था। डॉ. जेफ्रीज़, एक वैज्ञानिक और सर्जन, अमेरिका के पहले मौसम पर्यवेक्षकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 1774 से 1816 तक मौसम का रिकॉर्ड रखा। इसके अतिरिक्त, जेफ्रीज़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गुब्बारे उड़ाने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई और 1784 में अपना पहला गुब्बारा अवलोकन किया।

इस उत्सव के दौरान, सम्मानित लोग लगातार बदलते और अक्सर अप्रत्याशित मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने और रिपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नई तकनीकी प्रगति के बावजूद, मौसम विज्ञानियों को मौसम की भविष्यवाणी करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ भी, ₹माँ प्रकृति₹ की भविष्यवाणी करना और वह कौन सा रास्ता चुन सकती है, यह एक बहुत ही कठिन काम है। मौसम का पूर्वानुमान जानना हमारे लिए कई मायनों में मूल्यवान है। हम अक्सर आने वाले दिनों के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए पूर्वानुमान देखते हैं। यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कहाँ जाते हैं, या यहाँ तक कि हम जाते भी हैं या नहीं। आने वाले तूफ़ानों, तूफ़ानों या बवंडर के लिए तैयार रहना जान बचाता है।

मौसम विज्ञानी दिवस का निरीक्षण कैसे करें अपने स्थानीय मौसम विज्ञानी का धन्यवाद करें। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिससे आप नवीनतम तूफानों के बारे में अपडेट रहने के लिए समाचारों पर संपर्क करते हैं। या, यह राष्ट्रीय मौसम सेवा को रिपोर्ट करने वाले तूफान स्पॉटर भी हो सकते हैं। उनकी चेतावनियाँ हमें अधिक आसन्न खतरों के प्रति सचेत करती हैं। मौसम परिवर्तन अक्सर हमारे जीवन और आजीविका को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका समर्पण मूल्यवान है। विचार करें कि मौसम हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है और जब भी संभव हो सटीक पूर्वानुमान की आप कितनी सराहना करते हैं।

राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस का इतिहास यह दिन अमेरिका के पहले मौसम पर्यवेक्षकों में से एक डॉ. जॉन जेफ्रीज़ के जन्म की याद में मनाया जाता

सिरदर्द में उपयोगी स्वादिष्ट पाक

सिरदर्द के मुख्यतः दो कारण हैं- एक पित्त की अधिकता व दूसरा कब्ज। इसमें दीर्घकाल तक सतत दर्द रहता है अथवा महीने-दो महीने या इससे अधिक समय पर सिरदर्द का दौरा सा पड़ता है।

इसके निवारण के लिए-

500 ग्राम बादाम दरदरा कूट लें।

100 ग्राम घी में धीमी आँच पर सेंक लें।

750 ग्राम मिश्री की गाढ़ी, लच्छेदार चाशनी बनाकर उसमें यह बादाम, जावंत्री, जायफल, इलायची, तेजपत्र का चूर्ण प्रत्येक 3-3 ग्राम व 5 ग्राम प्रवालपिष्टी मिलाकर अच्छी तरह घोंट लें।

थाली में जमाकर छोटे-छोटे टुकड़े काटकर सुरक्षित रख लें।

10 से 20 ग्राम सुबह दूध अथवा पानी के साथ लें। (पाचनशक्ति उत्तम हो तो शाम को पुनः ले सकते हैं।)

खट्टे, तीखे, तले हुए व पचने में भारी पदार्थों का सेवन न करें।

बादाम अपने स्निग्ध व मृदु-विरेचक गुणों से पित्त व संचित मल को बाहर निकाल कर सिरदर्द को जड़ से मिटा देता है।

साथ में मस्तिष्क, नेत्र व हृदय को बल प्रदान करता है। अमेरिकन बादाम जिसका तेल, सत्त्व निकला हुआ हो वह नहीं, मामरी बादाम अथवा देशी बादाम भी अपने हाथ से गिरी निकाल से इस्तेमाल करो तो लाभदायक है। अमेरिकन बादाम का तेल गर्मी दे के निकाल देते हैं। बौद्धिक काम करने वालों के लिए तथा शुक्रधातु की क्षीणता व स्नायुओं की दुर्बलता में भी यह बादामपाक अतीव लाभकारी है।

स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सर्दियों में सेवन करने योग्य यह एक उत्तम पुष्टिदायी पाक है।

रांची एसएसपी चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह समेत छह को आईएएस में प्रोन्नति

कुपोषित राज्य के तीन बाल विकास महिला अफसर बनी आई ए एस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह समेत गैर प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति केन्द्र सरकार की कार्मिक मंत्रालय ने दे दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने संबंधित अधिसूचना वर्ष 2023 की प्रोन्नति लिस्ट जारी कर दी है। जिन्हें आईएएस में प्रोन्नति मिली है, उनमें रांची के एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह जो सीडिपीओं के पद पर रही उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिला है, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी व राजेश प्रसाद शामिल हैं। सिंह वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) हैं। सीता पुष्पा व प्रीति रानी भी सीडीपीओ हैं। इसी झारखंड राज्य से जहां कु पोषण की स्थिति पांच वर्ष से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चे महज कुपोषण के कारण नाटे हो जाते

है। 22 प्रतिशत बच्चे लम्बाई व वजन तथा 39 प्रतिशत कम वजन जो आंकड़ा विभाग को देश के लिए भी चिंता का विषय बनाए हुए हैं।

आगे इनके विषय में मिली जानकारी के मुताबिक बिजय कुमार सिन्हा ऊर्जा विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। धनंजय कुमार सिंह व राजेश प्रसाद श्रम एवं नियोजन विभाग के अधिकारी हैं। झारखंड सरकार के ये सारे मलाई के मामले में सदैव उर्जान्वित विभाग माने जाते हैं।

कौन सुने फरियाद...?

तुझे सताती होगी मेरी याद,
जालिम कौन सुने फरियाद।
नहीं मेरा प्यार कोई उन्माद,
दिल से तुझे करता हूँ याद।
घरवाले कहते है छोड़ नाद,
मुझे तू हर हाल में दे साथ।

तुझे सताती होगी मेरी याद,
जालिम कौन सुने फरियाद।
मैं यहाँ तू वहाँ है नजरबंद,
तेरा-मेरा जन्मों का अनुबंध।
इस रिश्ते में स्नेहिल है गंध,
कोई आकर खोल दे ये बंध।

तुझे सताती होगी मेरी याद,
जालिम कौन सुने फरियाद।
जीवन में ना हो ऐसे हालात,
कोई तो समझे मेरे जज्बात।
जब भी पूछे तुझसे सवालात,
कहो होगी हमारी मुलाकात।

संजय एम तराणेकर

रेलवे के डिब्बे से 12 विस्फोटक उपकरण मिला

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : बलांगीर जिले के कांटाबांजी स्टेशन पर आतंक फैल गया। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों को एक रेलगाड़ी के डिब्बे में 12 विस्फोटक उपकरण मिले। इस बात की जांच शुरू की गई कि यह विस्फोटक उपकरण किसने लगाया था। यह जानकारी खुदाई के दौरान सामने आई।गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह हर दिन की तरह बलांगीर जिले के कांटाबांजी रेलवे स्टेशन पर आने वाले रेलवे वैगनों की जांच की जाती है।रविवार को जब एक मालगाड़ी कांटाबांजी स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे अधिकारी एक वैगन में 12 विस्फोटक उपकरण देखकर हैरान रह गए। अचानक स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। बाद में इसे रेलवे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। बम जब्त होने के बाद यह पता लगाने के लिए जांच की गई कि यह कहां से आया और किसने बनाया। जब पता चला कि यह सायंताला बदामाल एम्युनिशन फैक्ट्री का बम है, तो कांटाबांजी स्टेशन पर मौजूद रेलवे

अधिकारी को आश्वस्त किया गया। बाद में 12 बमों को संबंधित फैक्ट्री में वापस कर दिया गया। दूसरी ओर, जब इस बात पर चर्चा हुई कि बम ट्रेन की बोगी में कैसे पहुंचा, तो प्रभारी कांटाबांजी स्टेशन प्रबंधक ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

चोयल परिवार द्वारा सम्मान समारोह आयोजित

सिकंदराबाद। मोलाली स्थित चोयल परिवार मोलाली द्वारा आयोजित अतिथियों के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में माधुराम, नेमीचन्द्र, सुरज, प्रकाश, जितेन्द्र चोयल उपस्थित गणमान्य अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना प्रदेश उपाध्यक्ष हुक्माराम सेपटा, सीरवी समाज तेलंगाना मल्लापुर अध्यक्ष तुलसाराम सिन्दडॉ, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा, श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सहसचिव ढगलाराम सेपटा, चेनाराम परिहार, पुनाराम हाम्बड़, भोमाराम चोयल, भंवरलाल चोयल, ज्ञानाराम चोयल, हापुराम गेहलोत, डवराराम गेहलोत, हेमाराम गेहलोत, जगदीश, सुखलाल परिहार, व समाज बंधु

किताबें मनुष्य की पथ-प्रदर्शक और नैतिक समर्थक !

पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होतीं हैं। पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ पुस्तकें हमें असीम आनंद, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भी सरोबार करतीं हैं। सच तो यह है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक, पथ-प्रदर्शक, प्रेरणा प्रदान करने वाली और नैतिक समर्थक साबित होतीं हैं, जो हमारे जीवन में हर मोड़ पर काम आतीं हैं। वास्तव में, किसी ने ग़लत नहीं कहा है कि किताबों के पन्नों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुज़रने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो। ये किताबें ही होतीं हैं जो हमें हमारी आसपास की दुनिया को सही से समझने, सही और गलत, अच्छा और बुरा, नैतिक और अनैतिक के बीच निर्णय लेने में हमारी भरपूर मदद करतीं हैं। पुस्तकें हमारे आदर्श, मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होतीं हैं। आज सूचना तकनीक और प्रौद्योगिकी के इस दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। यह ठीक है ये सभी तकनीकें अध्ययन के लिए हमें एक अच्छा विकल्प व सर्व-सुलभ विकल्प उपलब्ध करातीं हैं लेकिन ये तकनीकें किताबों के महत्व को कभी खत्म नहीं कर सकतीं हैं। जब हम किताबें/पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें अनेक नई जानकारियां मिलती हैं, हमारे ज्ञान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होती है। शायद यही कारण है कि एकबार पुस्तकों के बारे में गाँधीजी ने यह कहा था कि 'पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करतीं हैं।' बाल गंगाधर तिलक ने भी पुस्तकों के बारे में यह कहा था कि 'मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि जहां ये रहती हैं, वहां अपने आप ही स्वर्ग हो जाता है।'कहना ग़लत नहीं होगा कि लोकमान्य के इस कथन से पुस्तकों की महत्ता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। यहां तक कि अब्राहिम लिंकन ने पुस्तकों के बारे में यह कहा है कि 'मैं यही कहूंगा कि, वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मुझे ऐसी किताब दे जो आज तक मैंने न पढ़ी हो।' कहना ग़लत नहीं होगा कि 'विचारों के युद्ध में किताबें ही अस्त्र होतीं हैं।' बहरहाल, हाल ही में दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 1 फरवरी २०२५ को ५२ वें विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। हाल ही में निर्मित आधुनिक हॉल(भारत मंडपम) इस नौ-दिवसीय साहित्यिक उत्सव(पुस्तक मेले) के लिए स्थल होंगे, जो प्रदर्शकों और आगंतुकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि एनडीडब्ल्यूबीएफ २०२५ का आयोजन ९ फरवरी २०२५ तक होगा। बहरहाल, कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में जहां छपी पुस्तकों के प्रति क्रेज लगातार कम होता चला जा रहा है, ऐसे समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लेखकों-कलाकारों समेत युवा पाठकों और बच्चों तक को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वह अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। उल्लेखनीय है कि इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) द्वारा किया जाता है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन मेले का सह-आयोजक/स्थल भागीदार है।कई हजार स्क्वॉयर मीटर में फैले इस बुक फेयर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें भी देखने को मिलेंगी। इस बार अतिथि देश रूस है ,ऐसे में पाठकों को रूस के लेखकों और साहित्यकारों से भी मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। पाठक जानते होंगे कि इस मेले में साहित्य, शासन, टेक्नोलॉजी, कला और सिनेमा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के जाने-माने लोग शामिल हो रहे हैं। एनडीडब्ल्यूबीएफ २०२५ में एक नया सेगमेंट 'ऑथर्स लाउंज' बनाया गया है, जो लेखकों के लिए एक खास मंच होगा, जहां वो आपसी संवाद कर सकते हैं, सोच-विचार(चिंतन-मनन)कर सकते हैं और साहित्यिक उत्सव के बीच आराम भी कर सकते हैं। कहना चाहूंगा कि पुस्तक मेले पाठकों , लेखकों को निरंतर पढ़ने, लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें चुनने के लिए पुस्तकों का एक विस्तृत चयन प्रदान करते हैं, जिन्हें वे खरीदने का निर्णय लेने से पहले उन्हें देख सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। पुस्तक मेले विशेषकर बच्चों/युवाओं, यहां तक कि हर किसी में साहित्य और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देते हैं, क्यों कि पुस्तक मेले में अक्सर वर्कशॉप, कहानी सुनाने के सत्र, पैनल चर्चाएँ, संवादात्मक सत्र, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताएँ, आदि का आयोजन भी किया जाता है।प्रसिद्ध लेखकों और चित्रकारों के साथ-साथ शिक्षा और प्रकाशन क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा पुस्तक मेले में अनेक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और हर कोई पढ़ने लिखने को प्रोत्साहित होता है। इस मेले में लेखक कोना, बच्चों के लिए कोना, पेंटिंग कोना रखा गया है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जो बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने में सहायक सिद्ध होंगे।हाल फिलहाल जो पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजित किया गया है,वह निश्चित ही भारत ही नहीं दुनिया भर के प्रकाशकों, लेखकों और पाठकों को जोड़ेगा, क्यों कि इस पुस्तक मेले में इस बार 50 से अधिक देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ईरान, तुर्किये और स्पेन जैसे देश भाग ले रहे हैं, मतलब कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि हर साल की तरह इस साल भी बुक फेयर में दिव्यांग, स्कूल स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री में एंट्री होगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेले में २,000 से भी अधिक स्टॉल्स लगाये गये हैं तथा इस बार पुस्तक मेले की थीम 'रिपब्लिक @75' रखी गयी है, जो भारतीय गणराज्य के 75 साल पूरे होने के बारे में बताती है। वास्तव में थीम मंडप का मुख्य फोकस एक मजबूत भारत की परिकल्पना, राष्ट्र-निर्माण में प्रगति, और २047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर होगा।दूसरे शब्दों में कहें तो पुस्तक मेले की थीम रिपब्लिक@75 के साथ एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। यह कार्यक्रम साहित्य, शासन, प्रौद्योगिकी, कला और सिनेमा सहित विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि पांच दशकों की समृद्ध विरासत के साथ, यह पुस्तक मेला साहित्य, संस्कृति और ज्ञान का जीवंत संगम है। सच तो यह है कि ऐसे पुस्तक मेले के आयोजन से हर किसी में साहित्य, लेखन व लेखकों के प्रति गहरी समझ विकसित होती है। पाठकों को बताता चलूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा डिज़ाइन किया गया थीम मंडप इस पुस्तक मेले का केंद्र बिंदु होगा। यह मंडप रिपब्लिक @75 थीम को जीवंत करने के लिए क्रिएटिव्स, ग्राफिक्स, इंस्टॉलेशन, और कलाकृतियों का उपयोग करेगा। यहां आगंतुक पुस्तकों, विज़ुअल डिस्प्ले और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की 75 साल की यात्रा को देख और समझ सकेंगे। बहरहाल,आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी व संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार के युग के साथ ही आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर, इंस्टाग्राम में ही अधिक रम-बस गए हैं। हमें कोई भी सूचना, जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम इंटरनेट पर उसे सर्च करने लगते हैं और इंटरनेट के माध्यम से तमाम जानकारियां, सूचनाएं पल झपकते ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मौजूदा डिजिटल दौर में किताबों से सबसे ज्यादा उदासीन हमारे युवा ही हैं, ऐसे में, विश्व पुस्तक मेले का यह अभियान बहुत ही सराहनीय व काबिले-तारीफ है। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में पहला विश्व पुस्तक मेला जनपथ रोड के विंडसर प्लेस में 18 मार्च से चार अप्रैल, 197२ को लगा था, और तभी से इसकी लोकप्रियता में दिनों-दिन वृद्धि ही हुई है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल दौर में लोग पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है समय-समय पर ऐसे मेलों का आयोजन करके युवाओं को पुस्तकों से अधिकाधिक जोड़ा जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलकाता में हर साल आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला न केवल एशिया का सबसे बड़ा गैर-व्यावसायिक पुस्तक मेला है, बल्कि यह दुनिया में सबसे अधिक दर्शकों वाला पुस्तक मेला भी है। यह मेला आमतौर पर जनवरी के अंत से फरवरी की शुरुआत तक साल्ट लेक, कोलकाता के सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि इस साल 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला २८ जनवरी से ९ फरवरी, २०२५ तक बोईमेला प्रांगण, साल्ट लेक, कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है,जिसकी थीम देश जर्मनी है तथा जिसमें लगभग 1,000 स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोलकाता साहित्य महोत्सव शामिल किए गए हैं। जानकारी मिलती है कि यह मेला २० लाख (२ मिलियन) से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है, यह अपने आप में बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि लोग आज भी छपी हुई पुस्तकों को फिजीकल रूप से पढ़ने के प्रति गहरी रुचि दिखाते हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि पुस्तकें हमारे आदर्श, मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होतीं हैं और हमारी सच्ची पथ-प्रदर्शक भी। ये पुस्तकें ही होतीं हैं जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे काम आतीं हैं।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023